आज का विचार

तूफान का भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर।

दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ I मंगलवार, 31 मार्च, 2026 वर्ष 24, अंक 77, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

आप सरकार के दौरान शिक्षा क्षेत्र में पंजाब के स्कूलों ने बाजी मारी, राष्ट्रीय सर्वेक्षण में केरल को पछाड़कर अग्रणी बना पंजाब: भगवंत मान

4 सालों में शिक्षा बजट बढ़ाकर 19,279 करोड़ रुपए किया, 60 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले, 740 विद्यार्थियों ने जेईई परीक्षा और 1284 ने नीट परीक्षा पास की

यज्ञांश शर्मा
चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शानदार चार साल भगवंत मान दे नाल श्रृंखला के तहत पंजाब सरकार की शिक्षा क्रांति का चार सालों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस रिपोर्ट कार्ड में बताया गया कि निरंतर सुधारों के कारण सरकारी स्कूल मॉडल संस्थानों में बदल रहे हैं, जिसके देश भर में शानदार नतीजे सामने आ रहे हैं।

शिक्षा क्रांति को पंजाब के विकास की रीढ़ की हड्डी बताते हुए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष रैंकिंग, रिकॉर्ड शैक्षणिक नतीजे, जीरो पेपर लीक और बुनियादी ढांचे तथा शिक्षक प्रशिक्षण में किए गए बेमिसाल निवेश पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक वित्तीय प्रबंध किए गए हैं। वर्ष 2021-22 में शिक्षा बजट 12,657 करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़ाकर 19,279 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह आप सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता को दशार्ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शिक्षा रिपोर्ट कार्ड निरंतर जवाबदेही प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे पहले सिंचाई, स्वास्थ्य, खेल और कानून व्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी चार सालों की कार्यगुजारी संबंधी ऐसा रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया था और ये नतीजे शासन के सभी हिस्सों में सरकार द्वारा दिए जा रहे विशेष ध्यान को दिखाते हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए गए व्यापक सुधारों की रूपरेखा पेश की, जिसमें पिछले चार सालों में किए गए ढांचागत सुधार, रिकॉर्ड निवेश और नतीजों को उजागर किया गया। उन्होंने कहा, शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले देशों ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। हमारे देश में शिक्षा को निजी और सरकारी स्कूलों में बांट दिया गया था, जिससे शिक्षा में गहरा खाई पैदा हो गई। पिछली सरकारों ने स्कूलों को सिर्फ मिड-डे मील के केंद्रों तक सीमित कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, सरकारी स्कूलों में अब प्राइवेट स्कूलों के बराबर सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे माता-पिता को बेहतर विकल्प मिलेगा। एक अप्रैल से माता-पिता को उनके बच्चे की स्कूल से अनुपस्थिति और शिक्षकों की छुट्टी के बारे में भी सूचित किया जाएगा, जिससे हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। कई अन्य राज्यों खासकर गुजरात के उलट पिछले चार सालों में पंजाब में एक भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई, जो बेहद गर्व की बात है। प्रशासन में शिक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा

किसी भी राज्य या देश की तरक्की और खुशहाली में सबसे ज्यादा योगदान देती है। पिछले चार सालों में हमने इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। पहले स्मार्ट स्कूल के नाम पर लोगों और मासूम बच्चों को गुमराह किया गया था। स्कूलों को सिर्फ पेंट करके सुंदर बनाया जाता था, लेकिन उनमें उचित सुविधाएं या शिक्षकों की कमी रहती थी। आज पंजाब के सरकारी स्कूल निजी संस्थानों के बराबर खड़े हैं और हमारे शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है।

शिक्षा के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 19,279 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले साल से 7 प्रतिशत ज्यादा है। हम 3,500 करोड़ रुपए के साथ शिक्षा क्रांति के दूसरे चरण की शुरूआत कर रहे हैं। इसके तहत विश्व बैंक के साथ साझेदारी की गई है, जो इसे देश का सबसे बड़ा शिक्षा सुधार कार्यक्रम बनाता है। मुख्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पंजाब ने केरल को भी पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि गुजरात 16वें और हरियाणा लगभग 7वें या 8वें स्थान पर है। यह उपलब्धि हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों की है।

उन्होंने कहा, हाल के वर्षों में 740 विद्यार्थियों ने जेईई परीक्षा और 1284 ने नीट परीक्षा पास की है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने सर्वे में राष्ट्रीय औसत से 18 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

संस्थागत विस्तार के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 60 पहले ही कार्यशील हैं। ये स्कूल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं। पहली बार 24 लाख माता-पिता ने मेगा पी.टी.एम. में हिस्सा लिया है।

उन्होंने आगे कहा कि इन स्कूलों में 30,000 विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दियां प्रदान की गई हैं और मेडिकल व नॉन-मेडिकल समेत हर स्ट्रीम की पढ़ाई उपलब्ध है।

विकास और घुसपैठ प्रमुख चुनावी मुद्दे: मोदी

प्रधानमंत्री का असम के भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को असम के भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के माध्यम से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा-एनडीए की हैट्रिक जीत के लिए कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत करने की अपील की। उन्होंने विपक्षी दलों पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा असम की अस्मिता, सुरक्षा और संस्कृति से सीधे जुड़ा हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को नमो ऐप के जरिए 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' कार्यक्रम के तहत राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी दायित्व सौंपती है, उसे निभाने के लिए वे पूरी ताकत लगाते हैं। असम में भाजपा-एनडीए की हैट्रिक लगे, इसके लिए राज्य के पार्टी कार्यकर्ता जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने बोहाग बिहू और अन्य त्योहारों की तैयारियों के बीच चुनावी अभियान चलाने वाले कार्यकर्ताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि असम ने लंबे समय तक अस्थिरता, हिंसा और उग्रवाद का दौर देखा था, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार ने शांति, विकास और सुरक्षा का नया दौर

शुरू किया है। पिछले 10 वर्षों में 12 बड़े शांति समझौते हुए हैं जो असम की नई तस्वीर बनाते हैं।

संवाद के दौरान विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए। सुनितपुर जिले के पंकज हजारी ने कहा कि साल 2016 से पहले असम में अराजकता और उग्रवाद चरम पर था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद किसानों, व्यवसायियों और शिक्षकों के जीवन में अमूल्य परिवर्तन आया है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 18-22 साल के युवा मतदाता केवल पिछले 10 साल की शांति को जानते हैं, इसलिए बूथ कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि उन्हें पुराने दिनों की हिंसा और कांग्रेस की नीतियों की याद दिलाएं। भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर भजन संध्या, विरासत उत्सव और योजनाओं पर चर्चा के कार्यक्रम आयोजित करें ताकि नई पीढ़ी पुरानी गलतियों को दोहराने से बचे। तामलपुर जिले के धनेश्वर ने बोडोलैंड समझौते के बाद आए बदलाव को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि वह पार्टी कार्यकर्ता होने के साथ साथ वे व्यवसायी भी हैं। और राज्य के लोगों को पुरानी सरकार की कुरीतियों के बारे में बताते भी हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बोडोलैंड आज पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बन गया है, जहां पहले कर्फ्यू और धमाके होते थे, आज शांति और सांस्कृतिक धुनें गूंज रही हैं। उन्होंने कहा कि बंदूक छोड़कर कलम थामने वाले पूर्व उग्रवादियों और उनकी माताओं के अनुभव साझा करने के कार्यक्रम बूथ स्तर पर आयोजित करें। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की सूची बनाएं और उन्हें टोली बनाकर वोट डालने के लिए प्रेरित करें।

कार्यकर्ताओं ने मोदी को बताई राज्य की अहम समस्याएं

नौगांव जिले की दीपी दास ने कहा कि वह पिछले 9 साल से भाजपा के साथ लोगों की सेवा के लिए जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का लाभ मिला था। उसी धनराशि से उन्होंने जमीन लेकर तालाब बनवाया और मछली पालन शुरू किया। वह बच्चों को पढ़ाती भी हैं। वह भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं और लोगों को सरकार की तरफ से जागरुक भी कर रही हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति को नए असम की सबसे बड़ी ताकत बताया और अरुणोदय योजना, लखपति दीदी अभियान जैसी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देशभर में तीन करोड़ और असम में हजारों बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य है। महिलाओं के अनुभवों के शॉर्ट वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करें और बिहू के मौके पर पारंपरिक वस्त्रों जैसे गमोसा को बढ़ावा दें। वोटिंग के दिन परिवार की हर सदस्य को बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी। कारबियांग जिले के देवराज ने घुसपैठियों के मुद्दे को असम के लिए जीवन-मरण का विषय बताया। उन्होंने कहा कि वह पिछले 15 सालों से भाजपा कार्यकर्ता है। वह जोरशोर से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। राज्य में घुसपैठियों की बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि उनके जिले में हमेशा से घुसपैठ बहुत बड़ी चिंता रही है। कांग्रेस ने इन्हीं घुसपैठियों को वोटबैंक बना रखा है। उन्हें बांग्लादेश वापस खदेड़ने के लिए पूरा असम एक है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठ असम की पहचान, सुरक्षा, किसानों की जमीन, आदिवासियों की रोजी-रोटी और महिलाओं के सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि अवैध कब्जों की जानकारी रखें, पीड़ितों के वीडियो शेयर करें और लोगों को बताएं कि कांग्रेस ने अतिक्रमण दिया जबकि भाजपा अधिकार दे रही है। बाहर रह रहे युवा मतदाताओं को घर बुलाने और वोटिंग व्यवस्था बनाने को कहा। तिनसुकिया विधानसभा से चाय बागान क्षेत्र के अर्जुन ग्वाला ने भूमि पट्टे मिलने से मजदूरों में आए बदलाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वह भाजपा तिनसुकिया किसान मोर्चा के सचिव हैं। उनका चाय बागान है। वह राज्य में भाजपा को जिताने के लिए तत्पर हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि चाय बागान के लोग 200 साल से असम की पहचान हैं और भूमि पट्टा उनके बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव है।

लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी शब्बीर अहमद लोन गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक दुर्दान्त आतंकवादी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, लोन इस पूरे मॉड्यूल का हैंडलर था और हाल ही में सामने आए मेट्रो पोस्टर मामले में पकड़े गए आतंकी नेटवर्क को संचालित कर रहा था।

स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्पेशल सेल की नई दिल्ली रेंज के पुलिस उपायुक्त प्रवीण त्रिपाठी की देखरेख मे आतंकी को रविवार देर रात गाजीपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने बताया कि शब्बीर अहमद लोन के कब्जे से करीब 2,300 बांग्लादेशी टका, 3,000 से 5,000 पाकिस्तानी मुद्रा (लगभग 3,000 भारतीय रुपये के बराबर) और एक नेपाली सिम कार्ड मिला है। इन सभी सामानों को जब्त कर लिया गया है और उनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। जांच से यह भी सामने आया है कि लोन लंबे समय से बांग्लादेश में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। इससे पहले उसने हटियारा (कोलकाता) में अपने मॉड्यूल के लिए एक ठिकाना तैयार किया था, जो उसके सहयोगियों के लिए सेफ हाउस के तौर पर

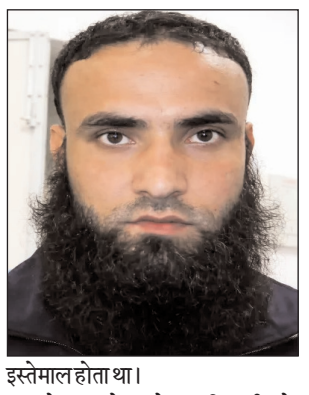

इस्तेमाल होता था।

स्पेशल सेल के अधिकारी के मुताबिक, यह ठिकाना आतंकी गतिविधियों के संचालन और सदस्यों के छिपने के लिए बेहद अहम था। यहीं से मॉड्यूल के सदस्यों को निर्देश दिए जाते थे और आगे की साजिशें रची जाती थीं। वहीं जांच एजेंसियों के अनुसार, शब्बीर लोन का फोकस उन इलाकों पर था जहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। वह ऐसे स्थानों की रेकी करता था, जहां अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। हाल के दिनों में भी उसने कई भीड़भाड़ वाले इलाकों का दौरा कर संभावित हमलों के लिए सर्वे किया था।

अधिकारियों का कहना है कि लोन का नेटवर्क काफी संगठित था और वह तकनीक का इस्तेमाल कर अपने सहयोगियों के संपर्क में रहता था। एन्क्रिप्टेड माध्यमों के जरिए बातचीत कर वह सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने की कोशिश करता था। पुलिस के मुताबिक, शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।

कट्टरपंथी बनाने और भर्ती का बड़ा नेटवर्क

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लोन का मुख्य काम बांग्लादेश में अवैध रूप से रह रहे लोगों और खासकर बांग्लादेशी नागरिकों को टारगेट कर उन्हें कट्टरपंथ की ओर धकेलना था। इसके बाद उन्हें भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार किया जाता था। आरोप है कि इन लोगों के फर्जी दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, बनवाकर उन्हें भारत के विभिन्न शहरों में छिपाया जाता था। सूत्रों के मुताबिक, इस मॉड्यूल ने दिल्ली सहित कई संवेदनशील इलाकों की रेकी भी की थी। खास तौर पर ऐतिहासिक स्थल लाल किला को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई से एक संभावित बड़े हमले को टाल दिया गया है।

आतंकी सरगनाओं से सीधे संपर्क

जांच में यह भी सामने आया है कि शब्बीर अहमद लोन के सीधे संबंध लश्कर के सरगना हाफिज सईद और उसके सहयोगी जकी-उर-रहमान लखवी से रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोन ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद स्थित आतंकी कैंप में प्रशिक्षण भी लिया था, जिसमें बेसिक (दौरा-ए-आम) और एडवांस (दौरा-ए-खास) ट्रेनिंग शामिल थी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना

एजेंसी (हि.स.)
गुवाहाटी/जागीरोड

असम के जागीरोड क्षेत्र के देवशाल में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक विशाल चुनावी सभा आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जागीरोड विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार पीयूष हजारिका के समर्थन में प्रचार किया।

सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार असम के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा असम और

पूर्वोत्तर के लगातार दौरों से क्षेत्र को नई पहचान मिली है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का इस तरह का जुड़ाव देखने को नहीं मिला।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में भूमिका की सराहना करते हुए जनता से अपील की कि विकास को गति देने के लिए पीयूष हजारिका को भारी मतों से विजयी बनाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के समय बाहरी निवेशक असम में निवेश करने से कतराते थे, लेकिन भाजपा के पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में निवेश का माहौल पूरी तरह बदल गया है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया, एनडीए उम्मीदवार रमाकांत देउरी, शशिकांत दास, डॉ. तपन दास, खलीलुर रहमान, अनिल सैकिया सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा में हजारों लोगों की उपस्थिति को लेकर उम्मीदवार पीयूष हजारिका ने कहा कि इससे उनका आत्मविश्वास और मजबूत हुआ है। उल्लेखनीय है कि, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन असम के दो दिवसीय दौरे पर रविवार को डिब्रूगढ़ पहुंचे थे। जहां उन्होंने मोहनबाड़ी हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इसके बाद वे चुनाव प्रचार करने तिनसुकिया जिले के मार्घेरिटा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे।

लोकसभा से दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक-2025 पारित

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

लोकसभा ने सोमवार को ध्वनि मत से हितधारकों के बीच व्याख्या संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए लाया गया दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक-2025 पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य दिवाला और दिवालियापन संहिता-2016 में और संशोधन करना है।

लोकसभा ने आज ध्वनि मत से 'इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक-2025' पारित कर दिया। यह विधेयक शुरू में एक प्रवर समिति के पास भेजा गया था। इसे इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में और संशोधन करने के लिए पेश किया गया है, ताकि कंपनियों और व्यक्तियों के बीच प्रक्रियागत देरी और व्याख्या संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके।

लोकसभा में दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025' पर हुई विस्तृत चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने

रखने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना था। सीतारमण ने चर्चा के दौरान कहा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) संशोधन विधेयक में कुल 12 संशोधन हैं, जिनमें से 11 चयन समिति के सुझाए गए हैं और एक सरकार ने पेश किया है। इस विधेयक के बारे में उन्होंने कहा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता देश के बैंकिंग क्षेत्र की सेहत सुधारने में खासकर स्ट्रेस्ड एसेट्स (तनावग्रस्त संपत्तियों) को सुलझाने में, एक अहम कारक रहा है।

सीतारमण ने लोकसभा में दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025' पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि दिसंबर, 2025 तक दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) ने 1,376 कंपनियों के समाधान में मदद की है, जिससे लेनदारों को 4.11 लाख करोड़ रुपये की वसूली हो पाई है। उन्होंने आगे कहा कि इस कानून का मकसद कभी भी सिर्फ कर्ज वसूली के एक जरिया के तौर पर काम करना नहीं था।

हरियाणा में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए जगह तलाशी जाएं, सभी सरकारी विभागों में भी इन्हें चालू किया जाएं: नायब सिंह सैनी

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा भर में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं जाने के लिए स्थान ढूंढने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान कई स्थानों पर जलभराव की समस्या सामने आती है, इसलिए इससे निपटने के लिए अभी से पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सोमवार को सचिवालय में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने बारिश से पहले होने वाली ड्रेन को सफाई, जल निकासी व्यवस्था और सफाई व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि जहां-जहां जल निकासी में दिक्कत है, उन स्थानों की पहचान कर वहां वैकल्पिक उपाय अपनाए जाएं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि ऐसे स्थानों पर वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के विकल्प तलाशे जाएं, ताकि वर्षा जल का संचयन हो सके और जलभराव की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में वॉटर हार्वेस्टिंग से जुड़ा पूरा और अपडेटेड डेटा तैयार किया जाए। इसमें यह जानकारी शामिल हो कि कहां-कहां वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हुए हैं, उनमें से कितने सही तरीके से काम कर रहे हैं और किन स्थानों पर इन्हें लगाने की आवश्यकता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी विभागों में इन सिस्टम्स को सही तरीके से लागू किया जाए और जहां यह अभी तक नहीं लगे हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर इन्हें स्थापित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों में इसे विशेष रूप से

लागू करना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में प्रदेश की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक, विशेष रूप से आरआईएफडी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कार्यों की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ी है। इस दिशा में लगातार सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जीपीएस आधारित कचरा कलेक्शन सिस्टम की भी समीक्षा की और इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रणाली में आरआईएफडी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कचरा संग्रहण की प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा रहा है। स्वीपिंग मशीनों की निगरानी को और मजबूत बनाने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा देते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन मशीनों पर चार कैमरे लगाए जाएंगे। एक आगे की ओर, एक ऊपर, एक नीचे और एक पीछे की ओर। उन्होंने कहा कि यदि सफाई के दौरान मशीन का नीचे लगा सेंसर बंद पाया जाता है, तो संबंधित एजेंसी को भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, अब एजेंसियों को हर महीने अपने बिल के साथ काम से संबंधित वीडियो फुटेज भी जमा करनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी जांच की जा सके। इसके साथ ही इस व्यवस्था में 1250 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, जिससे एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी और काम में लापरवाही नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों की सुविधाओं पर भी जोर देते हुए निर्देश दिए कि उन्हें ड्रेस, जूते और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि वे बेहतर तरीके से अपना कार्य कर सकें। खास बात यह है कि पूरे हरियाणा में कार्यरत सेनेटरी वर्करों के लिए एक जैसी ड्रेस लागू करने को मुख्यमंत्री ने कहा है। बैठक में गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में सफाई व्यवस्था, जल निकासी और पानी की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन शहरी क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरूण गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीणा, विभाग के निदेशक श्री मुकुल कुमार सहित विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे।

हिमाचल विस से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 58,830 करोड़ रुपये का बजट पारित

वित्तीय संकट: हर 100 रुपये में से सिर्फ 20 रुपये विकास पर

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 58,830 करोड़ रुपये से अधिक का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सदन में पेश हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 के पारित होने के साथ ही राज्य सरकार को इस राशि को खर्च करने की वैधानिक अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले 21 मार्च को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया था, जिसका प्रारंभिक आकार 54,928 करोड़ रुपये था, लेकिन अब संशोधित रूप में इसे बढ़ाकर 58,830 करोड़ 66 लाख 70 हजार रुपये कर दिया गया है।

सरकार के इस बजट में स्पष्ट संकेत है कि राज्य की बड़ी राशि अनिवार्य खर्चों पर जाएगी, जबकि विकास कार्यों

मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों तक का वेतन टला

के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध रहेंगे। बजट दस्तावेजों के अनुसार अगले वित्त वर्ष में सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर 100 रुपये में से लगभग 20 रुपये ही विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 27 रुपये वेतन, 21 रुपये पेंशन, 13 रुपये ब्याज अदायगी, 9 रुपये ऋण अदायगी और 10 रुपये स्वायत्त संस्थानों को अनुदान के रूप में खर्च किए जाएंगे।

राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने बजट में राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच अंतर को भी स्वीकार किया है। वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 40,361 करोड़ रुपये रहने का

अनुमान है, जबकि राजस्व व्यय 46,938 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। इस तरह 6,577 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित है। इसी तरह 9,698 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है, जो प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.49 प्रतिशत है। कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा निर्णय लेते हुए अपने वेतन का 50 प्रतिशत छह महीने के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों का 30 प्रतिशत तथा विधायकों का 20 प्रतिशत वेतन भी छह महीने के लिए स्थगित रहेगा। इसी अवधि के लिए निगमों और बोर्डों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सलाहकारों और ओएसडी का 20 प्रतिशत वेतन भी रोका जाएगा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिवों का 30 प्रतिशत वेतन स्थगित रहेगा, जबकि सचिवों से लेकर विभागाध्यक्ष स्तर तक के अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन छह महीने के लिए रोका जाएगा। पुलिस विभाग में डीजीपी और अतिरिक्त डीजीपी का 30 प्रतिशत तथा आईजी से एसपी स्तर तक के अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन स्थगित रहेगा। वन विभाग में भी पीसीसीएफ और अतिरिक्त पीसीसीएफ का 30 प्रतिशत तथा सीसीएफ से डीएफओ स्तर तक के अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन स्थगित रहेगा। हालांकि ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों के वेतन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अस्थायी व्यवस्था है और आर्थिक स्थिति सुधरने पर यह राशि वापस कर दी जाएगी। सरकार ने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से जुड़ी कई घोषणाएं भी बजट में शामिल की हैं।

हिमाचल पर कर्ज का बोझ बढ़कर 1.03 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा

एक साल में 10,966 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी: कैग रिपोर्ट

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ वर्ष 2024-25 के दौरान और बढ़ गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की वित्तीय रिपोर्ट (2024-25) के अनुसार राज्य की कुल देनदारियां एक साल में 10,966.89 करोड़ रुपये बढ़कर 1,03,331.91 करोड़ रुपये तक पहुंच गई हैं। इससे पहले 1 अप्रैल 2024 को राज्य पर कुल देनदारी 92,365 करोड़ रुपये थी। यह रिपोर्ट सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में पेश की।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार ने कुल 26,622.16 करोड़ रुपये के नए ऋण लिए, जबकि इसी अवधि में 18,168.80 करोड़ रुपये के पुराने कर्ज का भुगतान भी किया गया। इसके बावजूद कुल देनदारी में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो यह दिखाती है कि राज्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को लगातार नए कर्ज लेने पड़ रहे हैं। कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सार्वजनिक ऋण (पब्लिक डेब्ट) से जुड़ी देनदारियों में भी वृद्धि हुई है। यह देनदारी 8,328.94 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,842.47 करोड़ रुपये हो गई, यानी इसमें 2,513.53 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी तरह शुद्ध सार्वजनिक ऋण देनदारी 1 अप्रैल 2024 को 25,363.84 करोड़ रुपये थी, जो 31 मार्च 2025 तक बढ़कर 27,777.37 करोड़ रुपये पहुंच गई। रिपोर्ट में बाजार से लिए गए दीर्घकालिक कर्ज का भी जिक्र किया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार ने अलग-अलग किश्तों में कुल 10 दीर्घकालिक ऋण लिए। इनमें 550 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये, 150 करोड़ रुपये, 150 करोड़ रुपये, 400 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये, 300 करोड़ रुपये और 95 करोड़ रुपये के ऋण शामिल हैं। इन ऋणों पर ब्याज दरें 8.08 प्रतिशत से लेकर 9.63 प्रतिशत के बीच रहीं। कैग रिपोर्ट के मुताबिक इन ऋणों को बाजार से जुटाया गया और बाद में इनके भुगतान के लिए अधिसूचना जारी की गई।

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मु से की शिष्टाचार भेंट

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से शिष्टाचार भेंट कर राज्य के विकास एवं जनकल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी दोनों शीर्ष नेताओं के साथ पहली औपचारिक मुलाकात रही।

प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में चल रहे प्रमुख अभियानों नशा-मुक्त हिमाचल अभियान और टीबी-मुक्त हिमाचल अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन पहलों का उद्देश्य प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और सामाजिक कल्याण को सुदृढ़ करना है। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अग्रणी बताते हुए कहा कि राज्य में किसानों और बागवानों को रसायन-मुक्त खेती

अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने इस दिशा में और अधिक विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे प्रदेश में शून्य लागत, पर्यावरण-अनुकूल कृषि प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा, जो दीर्घकालिक पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय वृद्धि में सहायक होगी। कविन्द्र गुप्ता ने राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश में समग्र विकास, जनकल्याण और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे पूर्व राज्यपाल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी शिष्टाचार भेंट की।

हिमाचल में स्वास्थ्य कर्मियों के 3476 पद खाली

शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में पुरुष और महिला स्वास्थ्य कर्मियों के कुल 3476 पद खाली हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने विधायक विनोद कुमार के सवाल के लिखित जवाब में विधानसभा में दी। सरकार के अनुसार इनमें 1920 पद पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों के और 1556 पद महिला स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त हैं। मंत्री ने बताया कि फिलहाल इन पदों को भरने का मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है। हालांकि विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और रोगी मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों के पदों पर आखिरी बार वर्ष 2019 में 80 पदों के लिए भर्ती हुई थी। इसके बाद वर्ष 2022 में 3 पद और वर्ष 2023 में 1 पद के लिए भर्ती की गई थी। प्रदेश के कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में विभिन्न श्रेणियों के कुल 937 पद रिक्त हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में विधानसभा में दी। सरकार ने बताया कि 31 जनवरी 2026 तक बैंक में 937 पद खाली हैं और इन्हें भरने का मामला विचाराधीन है। इन पदों को बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार पंजीयक सहकारी सभाएं की पूर्व अनुमति के बाद बैंक के सेवा नियमों के तहत निदेशक मंडल द्वारा तय एजेंसी के माध्यम से भरेगा।

संगीत सदन ने मनाया पहाड़ी गीतकार व संगीतकार केआर पंछी का 90वां जन्मदिवस

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

संगीत को समर्पित संस्था संगीत सदन की ओर से मंडी के वरिष्ठ गीतकार, लोक साहित्य के मर्मज्ञ और संगीतकार केआर पंछी का 90वां जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खत्री सभा भवन में में आयोजित इस संगीतमय कार्यक्रम में सेवानिवृत सेशन जज तेजेंद्र नाथ वैद्य ने बतौर मुख्यअतिथि शिरकत की। जबकि खत्री सभा के अध्यक्ष डा. नरेश वैद्य बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे।

इस अवसर पर मंडी, सुंदरनगर और कुल्लू कांशीराम पंछी के पहाड़ी साहित्य और संगीत के प्रति योगदान को रेखांकित करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट किया और उनके स्वस्थ जीवन एवं दीघार्यु की कामना की। इस अवसर पर एक बड़ा केक भी काटा गया और प्रख्यात रचनाकार व संगीतकार केआर पंछी के दीघार्यु और स्वस्थ जीवन की कामना की गई। कार्यक्रम के आयोजक

संगीत सदन मंडी के संचालक उमेश भारद्वाज ने बताया कि के.आर. पंछी ने अपनी सारी रचनाओं को संगीतबद्ध कर मंच पर प्रस्तुत करने और उनको संरक्षित करने के अधिकार संगीत सदन को प्रदान किए गए हैं। जिसके चलते हर वर्ष संगीन सदन द्वारा उनके जन्मदिवस को परिवार के बुजूर्ग की तरह संगीतमय माहौल में मनाने की परंपरा शुरू की गई है। पेशे से अध्यापक रहे केआर पंछी का जन्म 29 मार्च 1936 को कुल्लू जिला के ऐतिहासिक गांव मंगलौर में हुआ। मंगलौर कई वर्षों तक मंडी रियासत के सेनवंश के राजाओं की राजधानी भी रहा है। पेशे से अध्यापक रहे केआर पंछी ने अब तक कुलवी, डोगरी, मंडयाली ,कांगड़ी और चम्बयाली बोली में लगभग 250 से अधिक गीतों की रचना कर उन्हें संगीतबद्ध भी किया है। उनकी रचनाओं में प्रदेश की विभिन्न बोलियों की झलक देखने को मिलती है, जिन्हें उन्होंने कविता, गजलों और गीतों के माध्यम से बेहद सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके शब्दों में लोक संस्कृति व प्रेम की गहराई और संगीत में सात सुरों की मधुरता साफ झलकती है।

उनके द्वारा लिखे बारामासा गीत - क्या दसिये जी , हो बछोड़े रे महीने कियां करी बीताए।

संक्षिप्त-समाचार

राजौरी में रहस्यमय परिस्थितियों में एक व्यक्ति मृत पाया गया

जम्मू। सोमवार को राजौरी के चकली इलाके में एक 25 वर्षीय युवक रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया जिसके बाद परिवार ने साजिश का आरोप लगाया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मृतक की पहचान चकली निवासी अमन शर्मा के रूप में हुई है। उसका शव चकली पुल के नीचे पड़ा मिला जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए शव को जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल राजौरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सात साल बाद विधानसभा की स्पीकर गैलरी में बैठी नजर आईं

जम्मू। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा का दौरा किया। विधानसभा में 2018 के बाद यह उनकी पहली उपस्थिति थी। सदन की कार्यवाही के दौरान मुफ्ती स्पीकर गैलरी में बैठी नजर आईं। उनका यह दौरा 2018 में उनकी सरकार गिरने के लगभग सात साल बाद हुआ है। उस समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन वापस लेने के बाद पीडीपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का अंत हो गया था। विधानसभा में मुफ्ती की उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा, क्योंकि यह 2018 के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद विधानसभा परिसर में उनकी पहली उपस्थिति थी। जम्मू-कश्मीर के इतिहास में 2018 को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, जबकि विश्लेषकों का कहना है कि इन घटनाक्रमों ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया था।

दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण केवल रोजगार का मुद्दा नहीं, बल्कि एक मानवीय मुद्दा : पारा

जम्मू। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और पुलवामा के विधायक वहीद-उर-रहमान पारा ने सोमवार को दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण को एक 'मानवीय मुद्दा' बताया और उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए पारा ने कहा कि लगभग एक लाख लोग अस्पतालों, एम्बुलेंस, पीएचई और सिंचाई सहित आवश्यक सेवाओं में काम कर रहे हैं और उनकी सेवाएं चौबीसों घंटे कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा यह केवल रोजगार या नियमितीकरण का मुद्दा नहीं है, यह एक मानवीय चिंता का विषय है। ये कर्मचारी दशकों से सेवा कर रहे हैं, फिर भी उनमें से कई को मान्यता और सुरक्षा से वंचित रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि उनके नियमितीकरण को सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक पहचान और एसआरओ प्रावधानों सहित पिछली पहलों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। पारा ने सभी राजनीतिक दलों से मतभेदों को भुलाकर नियमितीकरण के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 20-30 साल सेवा करने के बाद उन्हें यह कहना कि वे कर्मचारी नहीं हैं, एक विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि सरकार को करुणा के साथ काम करना चाहिए और दिहाड़ी मजदूरों को न्याय दिलाना चाहिए। उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों में शासन और पहुंच में सुधार के लिए नए जिलों और मंडलों के गठन सहित व्यापक प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

रियासी पुलिस ने कटरा में हेरोइन के साथ ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार

रियासी। नशीले पदार्थों के खिलाफ निरंतर अभियान और नशामुक्त समाज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पुलिस रियासी ने एक और सफलता हासिल की जब कटरा के जीजी चौक पर एक विशेष नाका लगाया गया। नाके की जांच के दौरान कटरा के चाय बागान निवासी विपिन शर्मा पुत्र दिव्यांश शर्मा को नियमित जांच के लिए रोका गया। उसकी तलाशी लेने पर, पुलिस दल ने उसके पास से 3 ग्राम हेरोइन (चिट्टा जैसा पदार्थ) बरामद की। त्वरित कार्रवाई करते हुए कटरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 86/2026 धारा 8/21/22 एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज की गई है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

मेडिकल भत्ते में बढ़ोतरी की मांग, एनएमसी ने उठाई आवाज

जम्मू। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस (एनएमसी) के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री से पेंशनर्स के मासिक मेडिकल भत्ते को 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की जोरदार मांग की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगामी जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाना चाहिए। एनएमसी कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए शास्त्री ने कहा कि दवाइयों और चिकित्सा खर्चों में पिछले दो दशकों में भारी वृद्धि हुई है, जिसके चलते यह मांग पूरी तरह जायज है। उन्होंने बताया कि लद्दाख में अप्रैल 2020 से ही पेंशनर्स को 1000 रुपये मासिक मेडिकल भत्ता दिया जा रहा है, जबकि जम्मू-कश्मीर में अभी भी केवल 300 रुपये ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बजट में पेंशनर्स की इस मांग को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा शास्त्री ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीनों के लंबित डीए एरियर जारी करने की भी मांग की। शास्त्री ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से अपील करते हुए कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए रोके गए तीन डीए किस्तों के बकाये को जल्द जारी किया जाए। साथ ही 1 जनवरी 2026 से देय 3 प्रतिशत डीए भी लागू किया जाए। उन्होंने सरकार से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और उनसे किए गए वादों को पूरा करने की भी मांग की।

हिमाचल में वेतन स्थगन पर डॉक्टरों का विरोध, सरकार को चेतावनी

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के वेतन के प्रस्तावित स्थगन के मुद्दे पर अब मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों ने भी विरोध जताया है। आईजीएमसी शिमला के कंसल्टेंट डॉक्टरों की संस्था सीनियर एकेडमिक मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन (सैमडकॉट) ने इस संबंध में जनरल हाउस की बैठक बुलाकर राज्य सरकार से वेतन स्थगन के प्रस्ताव को तुरंत वापस लेने की मांग की है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि डॉक्टरों और मेडिकल शिक्षकों से जुड़े लंबित मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो इसका असर मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ सकता है।

सैमडकॉट की बैठक में डॉक्टरों ने कहा कि ग्रुप-ए और ग्रुप-बी

कर्मचारियों के वेतन में 20 से 30 प्रतिशत तक कटौती या स्थगन का प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन उनका अधिकार होता है और इसे स्थगित करना उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डाल सकता है। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि पिछले कई वर्षों से संशोधित वेतनमान के एरियर और करीब 15 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान भी लंबित है, ऐसे में वेतन स्थगन का प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए और कठिनाई पैदा करेगा। डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेजों में पदोन्नति से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। सैमडकॉट का कहना है कि अगस्त 2022 के बाद से राज्य में किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर नियमित पदोन्नति नहीं हुई है। इससे वरिष्ठ शिक्षकों में निराशा बढ़ रही है और उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि लंबे समय तक पदोन्नति नहीं होने से मेडिकल शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है।

डॉक्टरों ने यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल और चिकित्सा शिक्षा निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को सेवा विस्तार देकर नियुक्त किया जा रहा है, जबकि पात्र और वरिष्ठ संकाय सदस्य पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि यह व्यवस्था प्रशासनिक पारदर्शिता और संस्थागत व्यवस्था दोनों को प्रभावित करती है।

हरियाणा के श्रद्धालुओं का ट्रैक्टर पलटा, 12 घायल, एक पीजीआई रैफर

ऊना। बंगाणा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत पीरनिगाह-मकरैड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्राली पलट गई। हादसे में 12 श्रद्धालु घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में दाखिल करवाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने कुशल (20) पुत्र अवतार सिंह निवासी मजारी जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा) को प्राथमिक उपचार देकर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही ऊना पुलिस टीम भी मौका पर पहुंची और आगामी जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार कुरुक्षेत्र (हरियाणा) से श्रद्धालुओं का जत्था ट्रैक्टर-ट्राली में बैठकर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर शीश नवाने आया था। श्रद्धालुओं ने बीते दिन ही बाबा बालक नाथ मंदिर में शीश नवाया था। सोमवार को श्रद्धालु माता नैना देवी मंदिर में शीश नवाने जा रहे थे। श्रद्धालु जब पीरनिगाह-मकरैड़ रोड़ पर जा रहे थे तो अचानक ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर सडक के बीचों-बीच पलट गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर श्रद्धालुओं की चीखों-पुकार मच गई। इस दौरान सडक पर जा रहे अन्य लोगों ने इंसानियत का परिचय देते हुए घायल हुए श्रद्धालुओं की मदद शुरू कर दी। लोगों ने ट्रैक्टर-ट्राली के नीचे से श्रद्धालुओं को बाहर निकाला और उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया।

कोटखाई में चिट्टे के साथ दो गिरफ्तार, पिस्टल भी बरामद

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस ने शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में चिट्टा बेचने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चिट्टा के साथ एक पिस्टल, चाकू और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार रविवार शाम थाना कोटखाई के तहत कोकुनला के पास काले रंग की टाटा सफारी गाड़ी में सवार दो लोग चिट्टा बेचते हुए पकड़े गए।

आरोपियों की पहचान रमन जीत (50 वर्ष), निवासी मोहाली (पंजाब) और रूबेल (26 वर्ष), निवासी गांव ताकरोट डाकघर बगैर कोटखाई के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2.25 ग्राम चिट्टा, एक पिस्टल, एक छोटा चाकू और दो अतिरिक्त गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट की

विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी नशे की सप्लाई कहां से ला रहे थे और किन लोगों तक पहुंचा रहे थे। इसी बीच शिमला जिले के ही चौपाल क्षेत्र में पुलिस ने एक अन्य कार्रवाई में एक व्यक्ति को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक थाना चौपाल के तहत चंबी क्षेत्र के ननाहर मोड़ के पास पुलिस टीम ने नरेंद्र सिंह उर्फ भूरा (46 वर्ष), निवासी गांव गागना डाकघर चंबी तहसील चौपाल को 90 ग्राम चरस के साथ पकड़ा है।

इस मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत केस दर्ज किया गया है।

पंडोह में 25 महिलाओं ने सिखी ब्यूटी पार्लर की बारिकियां, 35 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंडी जिला के पंडोह में आयोजित 35 दिवसीय स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया । इस प्रशिक्षण शिविर में स्थानीय महिलाओं को ब्यूटी पार्लर की बेसिक ट्रेनिंग दी गई। पंजाब नेशनल बैंक के सौजन्य से स्वरोजगार ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान स्योगी पंडोह में यह प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें क्षेत्र की लगभग 25 महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर की बारिकियां सिखी। इस शिविर में प्रशिक्षिका अंजना कुमारी ने महिलाओं को ब्यूटी पार्लर से संबंधित थ्रेडिंग, वैक्सिंग, मैनीक्योर, पेडीक्योर, फेशियल, कैराटीन इत्यादि करना सिखाया। जिससे अब यह महिलाएं भी इस स्किल के माध्यम से स्वरोजगार को अपना सकती हैं।

इस मौके पर स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी निदेशक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि बीते 23 फरवरी को इस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ था। पीएनबी बैंक के सौजन्य से इन महिलाओं को ब्यूटी पार्लर का बेसिक कोर्स करवाया गया। 35 दिन के इस प्रशिक्षण का इन महिलाओं को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। प्रशिक्षका अंजना कुमारी ने बताया कि साल 2024 में उन्होने भी आरसेटी से ही यही कोर्स किया था और आज वे इस स्किल के साथ अपना व्यवसाय भी कर रही हैं। साथ ही समय समय पर आरसेटी केंद्र में प्रशिक्षिका के तौर पर अपनी सेवाएं भी दे रही है। इस अवसर पर प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने पहुंची प्रशिक्षु महिलाओं में गीता देवी ओर सुमन ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि इस शिविर के माध्यम से उन्हें ब्यूटी पार्लर की बारिकियों को जानने का अवसर मिल पाया है। भविष्य में वे भी अब इस स्किल को स्वरोजगार के तौर पर अपना कर आत्मनिर्भर बनना चाहेंगी।

मौसम | **मौसम विभाग ने 5 अप्रैल तक खराब मौसम की जताई संभावना**

हिमाचल में अंधड़, ओलावृष्टि और आसमानी बिजली का अलर्ट

ठंड बढ़ी, शिमला-मंडी सहित 8 जिलों में भारी चेतावनी जारी

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में मौसम के तेवर कड़े बने हुए हैं और राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड का असर बढ़ गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में रुक-रुक कर बर्फबारी हो रही है, जबकि कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 5 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है और कई जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि तथा आसमानी बिजली को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

राज्य के लाहौल-स्पीति जिले के मुख्यालय केलंग में 2 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। इसके अलावा रोहतांग दर्रे सहित किन्नौर, कुल्लू और चंबा की ऊंची चोटियों पर भी हिमपात

हुआ है। शिमला, मनाली और अन्य मध्य व निचले इलाकों में सुबह से बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो सराहन में 32.7 मिमी, कसौली में 32.0 मिमी, धर्मपुर में 27.6 मिमी, पच्छाद में 20.4 मिमी, सोलन में 18.4 मिमी, मनाली में 14.0 मिमी, सेओबाग में 11.4 मिमी, रोहड़ू में 10.0 मिमी, कंडाघाट में 8.4 मिमी, भुंतर में 7.8 मिमी और धर्मशाला में 7.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा शिमला में 4.4 मिमी और सुंदरनगर में 4.0 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश के औसतन न्यूनतम तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान शिमला में 11.8 डिग्री, सुंदरनगर में 12.1 डिग्री, भुंतर में 9.3 डिग्री, कल्पा में 3.0 डिग्री, धर्मशाला में 9.5 डिग्री, ऊना में 15.3 डिग्री, नाहन में 15.3 डिग्री, केलंग में 1.5 डिग्री, पालमपुर में 13.5 डिग्री, सोलन में 11.0 डिग्री, मनाली में 7.1 डिग्री, कांगड़ा में 15.2 डिग्री, मंडी में 13.3 डिग्री और बिलासपुर में 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंड बढ़ने से पहाड़ी इलाकों में लोग फिर से गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं, जबकि मैदानी और निचले क्षेत्रों में भी मौसम ठंडा बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज कई स्थानों पर अंधड़, ओलावृष्टि और आसमानी बिजली के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर अन्य आठ जिलों में आज अलर्ट रहेगा। इनमें शिमला, मंडी और कुल्लू में ओलावृष्टि, आसमानी बिजली व 40 से 60 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से आंधी चलने का ओरेंज अलर्ट रहेगा। जबकि कांगड़ा, चम्बा, हमीरपुर, बिलासपुर व ऊना में येलो अलर्ट रहेगा। इसके बाद 31 मार्च को कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक और 2 अप्रैल को मौसम खराब रहेगा, लेकिन किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं 3 और 4 अप्रैल को फिर से कई जिलों में अंधड़ और आसमानी बिजली की चेतावनी जारी की गई है। 5 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का
न्वोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा कर दिए अहम निर्देश

दवा का रिकॉर्ड होगा रियल टाइम सेंट्रलाइज्ड, डॉक्टर ने अगर बाहर की दवा लिखी तो कार्रवाई होगी: मुख्यमंत्री

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए है कि सरकारी अस्पतालों में दवा का रिकॉर्ड रियल टाइम सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर होगा। किस अस्पताल में कौन सी दवा उपलब्ध हैं, उस बारे में चिकित्सक को बताया जाएगा। ताकि बाहर की दवा लिखने की गुजाइंश न बचे, अगर फिर भी किसी डॉक्टर द्वारा बाहर से मिलने वाली दवा किसी मरीज की ओपीडी स्लीप पर लिखी जाती है, तो डॉक्टर उस बारे में अस्पताल में दवा उपलब्ध न होने की बात लिखेंगे। इतना ही नहीं, इस कार्य के लिए सीएमओ की जवाबदेही तय होगी।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक एवं विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारिओं को सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सा उपकरणों की स्थिति, ओपीडी प्रबंधन, डॉक्टरों व स्टाफ की तैनाती, दवा एवं उपकरणों की खरीद प्रक्रिया तथा मरीजों को दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिशित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल आने वाले मरीज को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाओं पर सतत निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और सभी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं, उपकरणों एवं सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमीं की स्थिति किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों में दवाओं के स्टॉक की रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि दवाओं की उपलब्धता पर निरंतर नजर रखी जा सके और आवश्यकतानुसार समय रहते आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवा की खरीद इत्यादि को

लेकर 1 साल के लिए पैनल इत्यादि की व्यवस्था की जाएं। सीएमओ 4 दिन पहले ही पैनल संबंधित एजेंसियों को दवा उपलब्धता बारे बता दें, ताकि किसी अस्पताल में दवा की कमीं न रहे।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अनावश्यक रूप से बाहर की दवाइयां लिखने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखा जाए। इस संबंध में तय दिशा-निदेर्शों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएं, ताकि मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े और उन्हें सरकारी अस्पतालों में ही समुचित उपचार मिल सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई सहित अन्य उन्नत चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए जानकारी ली और बताया गया कि 10 जिलों में आवश्यक अपडेट पूरे किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने शेष 12 जिलों में इन सुविधाओं से संबंधित कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों को उच्च स्तरीय जांच सुविधाओं के लिए अन्य जिलों में न जाना पड़े और उन्हें अपने ही जिले में बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य ढांचे का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाए।

बैठक के दौरान अस्पतालों में मरीजों की संख्या के अनुरूप व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मरीजों को समय पर उपचार मिलना चाहिए। इसके लिए आवश्यकतानुसार स्टाफ की तैनाती, ड्यूटी रोस्टर और कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बैठक में मुख्यमंत्री को बताया कि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की नियुक्ति बारे भी दिशा निर्देश दिए जा चुके है, जब तक फुल टाइम स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की तैनातनी नहीं होती, तब तक कांट्रेक्ट पर चिकित्सों की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सिविल सर्जन यानि सीएमओ की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएं। यह भी निर्देश दिए कि जिलों में तय लक्ष्यों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित किया जाए और प्रदर्शन आधारित निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में दवाओं, उपकरणों और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रोक्योरमेंट प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दवाओं और उपकरणों की खरीद में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जाएं। इसके साथ ही, गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और आवश्यकतानुसार बेहतर प्रथाओं को अपनाने पर भी जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में साफ-सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने और मरीजों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में स्वच्छ वातावरण, सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं और मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने फीडबैक तंत्र को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया, ताकि मरीजों के अनुभव के आधार पर सेवाओं में निरंतर सुधार किया जा सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश के मेडिकल कॉलेज की प्रगति, ई-उपचार सेवा, आयुष्मान योजना के साथ साथ युद्ध के इस माहौल में दवा के स्टॉक, एबुलैंस में तेल की व्यवस्था और अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाले खाने इत्यादि की व्यवस्था के लिए एलपीजी उपलब्धता बारे भी चर्चा हुई। जिस पर अधिकारियों ने बताया कि इस दिशा में ठोस कदम उठाये गए है, तथा किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के सचिव एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के मिशन निदेशक श्री आरएस ढिल्लो, स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेश डॉ. मनीष बंसल सहित अधिकारीगण मौजूद थे।

सांसद सैलजा ने सरकार के तुगलकी फरमान पर उठाए सवाल

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

किसानों की समस्याओं को बताया चिंताजनक

सिरसा की सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार द्वारा मंडियों में फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर बायोमेट्रिक अनिवार्यता और अन्य नई शर्तें लागू करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे किसानों पर थोपा गया तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि यह निर्णय किसानों की समस्याओं को कम करने के बजाय और बढ़ाने वाला है। कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश का किसान पहले ही मौसम की मार, बढ़ती लागत, खाद-बीज की महंगाई और समय पर भुगतान न मिलने जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा जटिल डिजिटल प्रक्रियाएं थोपना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि छोटे और सीमांत किसान तकनीकी प्रक्रियाओं से पूरी तरह परिचित नहीं हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और संसाधनों की कमी के कारण मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना उनके लिए बेहद कठिन हो जाता है। उन्होंने बताया कि कई किसान अभी तक पंजीकरण नहीं करवा पाए हैं, जिससे वे अपनी मेहनत की फसल बेचने से वंचित रह सकते हैं। मंडियों में पहले से ही लंबी कतारें, टोकन प्रणाली में देरी और भुगतान में विलंब जैसी समस्याएं मौजूद हैं। अब बायोमेट्रिक, ट्रैक्टर-ट्रॉली नंबर अंकन और फोटो जैसी नई शर्तों के कारण किसानों को कई दिनों तक मंडियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जिससे उनकी आर्थिक और मानसिक परेशानी और बढ़ेगी। कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि धान खरीद में हुई गड़बड़ियों और घोटालों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों और व्यापारियों पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार किसानों को ही परेशान कर रही है। यह स्थिति करे कोई, भरे कोई को दशार्ती है।

नाटक राम नाम सत्य है ने दिखाई जिंदगी और मौत के बीच की बेबसी

सिटी दर्पण संवाददाता

कुरुक्षेत्र

विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा कला परिषद द्वारा कला कीर्ति भवन की भरतमुनि रंगशाला में आयोजित तीन दिवसीय रंगरथ नाट्य महोत्सव का रविवार को समापन हो गया। कला परिषद के निदेशक विवेक कालिया के दिशा-निर्देश में 27 मार्च से शुरू हुए महोत्सव में पहले दिन सफीदों जींद के कलाकारों ने ऐतिहासिक नाटक सम्राट अशोक का मंचन किया। वहीं दूसरे दिन दिल्ली के कलाकारों ने हास्य नाटक घर का न घाट का मंचित कर कुरुक्षेत्र वासियों को खूब गुदगुदाया। उत्सव के समापन पर मीरा कल्चर सोसायटी भिवानी के कलाकारों द्वारा चंद्रशेखर फणसलकर का लिखा और सोनू रोंझिया के निर्देशन में नाटक राम नाम सत्य है मंचित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन विकास शर्मा द्वारा किया गया। नाटक मंचन से पूर्व वरिष्ठ मीडियाकर्मी विनोद शर्मा तथा रजनीश गुप्ता सहित सुरेखा मखीजा, नीरज सेठी और धर्मपाल गुगलानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

नाटक राम नाम सत्य है में कलाकारों ने एडस जैसे रोग से ग्रस्त और नशे की लत में पड़े लोगों की मनोदशा को दिखाया। गोपीनाथ की कहानी के माध्यम से कलाकारों ने दिखाया किस तरह गोपीनाथ एक सभ्य व्यक्ति से नशे की गिरफ्त में चला जाता है और उसकी जिंदगी बर्बाद होनी शुरू हो जाती है। कलाकारों के सशक्त अभिनय और संवेदनशील संवादों के कारण नाटक पूर्णतया रोग और नशे के कारण जिंदगी व मौत के बीच फैली बेबसी को दिखाने में कामयाब रहा। कलाकारों ने बेहद संजीदगी के साथ अपने अपने किरदारों को प्रस्तुत किया। नाटक ने जहां एड्स रोगियों की मानसिक असंतुलित स्थिति और जिंदा रहने की बेबसी को बयान किया, वहीं उनके मन की पीड़ा, घबराहट और मादक पदार्थों से नशे की गिरफ्त में फंसकर खराब फेफड़ों के साथ मौत की राह पर चलकर जिंदा रहने का लालच भी साफ नजर आया। नाटक जीवन, मृत्यु और सामाजिक यथार्थ के गहरे प्रश्नों को छूता नजर आया। मानवीय संवेदनाओं, रिश्तों और समाज की कड़वी सच्चाइयों को भावनात्मक और सधे हुए अंदाज में प्रस्तुत करते हुए कलाकारों ने दर्शकों की भरपूर वाहवाही बटौरी। नाटक में अनूप कुमार, पुलकित आर्य, अमन कुमार, आस्था दहिया, नवीन, इशिका गोयल, ओमप्रकाश, अंकित कुमार, सचिन, आदित्य, अरुण ने सहयोग दिया। संगीत संचालन सोनू रोंझिया ने तथा प्रकाश व्यवस्था विश्वजीत ने सम्भाली। नाटक के अंत में सोनू रोंझिया को हरियाणा कला परिषद की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

28 वर्ष 4 माह की उत्कृष्ट सेवाओं के बाद रणबीर सांगवान सेवानिवृत्त

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग मुख्यालय के अतिरिक्त निदेशक (फील्ड) श्री रणबीर सिंह सांगवान 28 वर्ष 4 माह की संतोषजनक एवं समर्पित सेवा पूर्ण करने के उपरांत आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर विभाग द्वारा उनके सम्मान में एक गरिमामयी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद. पांडुरंग, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खाँगवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्री सांगवान को भावभीनी विदाई देते हुए उनके स्वस्थ, सुखद एवं समृद्ध सेवानिवृत्त जीवन की कामना की। वक्ताओं ने उनके अनुशासित कार्यशैली, समर्पण और सौम्य व्यवहार की सराहना करते हुए विभाग में उनके योगदान को प्रेरणादायक बताया।

श्री सांगवान मूल रूप से चरखी दादरी जिले के झोझू खुर्द गांव के निवासी हैं। उन्होंने केन्द्रीय विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की और 21 नवंबर, 1997 को जनसम्पर्क अधिकारी के रूप में विभाग में अपनी सेवाएं आरंभ कीं। अपने करियर की शुरूआत उन्होंने विभाग की प्रेस शाखा से की, जिसके बाद उन्होंने सिरसा, जींद, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम एवं फतेहाबाद जैसे विभिन्न जिलों में जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी के रूप में उत्कृष्ट सेवाएं दीं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर उनकी मजबूत पकड़ तथा उनका मृदुभाषी व्यक्तित्व उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाता रहा। वर्ष 2012 में उन्हें उपनिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके उपरांत उन्होंने हरियाणा भवन, नई दिल्ली तथा एनसीआर में उपनिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं।

अतिरिक्त निदेशक (फील्ड) के रूप में उन्होंने विभिन्न अतिविशिष्ट राजनेताओं एवं प्रमुख हस्तियों के कार्यक्रमों के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे विभाग की कार्यक्षमता और छवि को नई ऊंचाइयां मिलीं। विदाई समारोह में सयुंक्त निदेशक श्री राजसिंह कादियान, श्री नीरज टुटेजा, पूर्व अतिरिक्त निदेशक डॉ. कुलदीप सैनी, डॉ. साहिब राम गोदारा, श्री बी.एल. धीमान, सहित विभाग के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

हिसार के आईएमसी प्रोजैक्ट में आई तेजी

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनने की राह पर हरियाणा

हिसार में विकसित किए जा रही इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) परियोजना के दम पर हरियाणा देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है। लगभग 2,988 एकड़ क्षेत्र में फैली यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-52 और राष्ट्रीय राजमार्ग-09 से जुड़ी है तथा प्रस्तावित हिसार एविएशन हब के निकट स्थित है। आईएमसी को अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के तहत विकसित किया जा रहा है, जिससे हिसार को राष्ट्रीय औद्योगिक नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां परियोजना की प्रगति की समीक्षा की।

संबंधित विभागों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि हिसार आईएमसी परियोजना प्रदेश के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मजबूत संस्थागत सहयोग, रणनीतिक योजना और प्रभावी क्रियान्वयन के बल पर यह परियोजना निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित मास्टर प्लान के अनुसार लगभग 61 प्रतिशत भूमि औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स गतिविधियों के लिए निर्धारित की गई है, जबकि शेष क्षेत्र हरित क्षेत्र, उपयोगिताओं और बुनियादी ढांचे के लिए रखा गया है। परियोजना में एयरोस्पेस एवं रक्षा, इंजीनियरिंग एवं फैब्रिकेशन, खाद्य प्रसंस्करण, परिधान उद्योग तथा लॉजिस्टिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिससे विविध और सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

परियोजना के लिए शत-प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है तथा नेशनल प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) से स्वीकृति समेत प्रमुख स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। चरण-1 के लिए पर्यावरण स्वीकृति भी मिल चुकी है। कच्चे पानी के जलाशय का निर्माण, कैनाल री-एलायनमेंट तथा विद्युत आपूर्ति योजना जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचना कार्यों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। एक हाई वोल्टेज विद्युत लाइन को हटाया जा चुका है और शेष कार्य भी तेजी से प्रगति पर हैं, ताकि अवसंरचना विकास निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके।

बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी. अनुपमा, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, उद्योग एवं वाणिज्य के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, एचवीपीएनएल के प्रबंध निदेशक डॉ. आदित्य दहिया और एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री सुशील सारवान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

हरियाणा में रेल कनैक्टिविटी का नया दौर, एचओआरसी टनल का 61 फीसदी कार्य पूरा

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम (एचआरआईडीसी) हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को नई दिशा देने जा रहा है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक और प्रस्तावित ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर समेत एचआरआईडीसी की तमाम परियोजनाएं लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने, औद्योगिक विकास को गति देने और हरियाणा को देश के प्रमुख अवसंरचना केंद्र के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएंगी।

हरियाणा के मुख्य सचिव एवं एचआरआईडीसी के अध्यक्ष श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज यहां हुई निदेशक मंडल की 34वीं बैठक में प्रदेश की प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि मंत्रिमंडल द्वारा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (एचओआरसी) परियोजना की संशोधित लागत लगभग 11,709 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है, जबकि पहले स्वीकृत लागत 5,618 करोड़ रुपये थी। यह कॉरिडोर खरखौदा, मानेसर और सोहना जैसे प्रमुख औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स केंद्रों को निर्बाध रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में नए टाउनशिप के विकास को भी गति देगा। यह परियोजना माल ढुलाई को तेज करने, परिवहन समय कम करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, परियोजना की 7,070 मीटर लंबी टनल में से 4,349 मीटर यानी लगभग 61 प्रतिशत खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। यह कार्य न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (एनएटीएम) के माध्यम से किया जा रहा है। यह टनल एचओआरसी परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी तेज प्रगति समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रति एचआरआईडीसी की प्रतिबद्धता को दशार्ती है। परियोजना के लिए सभी प्रमुख पर्यावरण और वन स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं, जिससे महत्वपूर्ण नियामकीय बाधाएं दूर हो गई हैं। चरण-1 के तहत वन स्वीकृति अक्टूबर 2025 में प्रदान की गई थी, जबकि गांव रोजका मेव में टनल एलाइनमेंट के लिए स्वीकृति 4 मार्च, 2026 को मिल चुकी है। इसके अलावा 20 मार्च, 2026 को अरावली स्वीकृति भी मिल गई है, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आई है।

हितधारकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए एचआरआईडीसी ने पांच जिलों के भूमि मालिकों को कुल 2,273 करोड़ रुपये के मुआवजे में से 1,929 करोड़ रुपये, यानी लगभग 85 प्रतिशत राशि वितरित कर दी है। गुरुग्राम में 99 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है, जबकि नूंह में 94 प्रतिशत मुआवजा वितरित किया गया है। निजी भूमि के लिए 1,346 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जो कुल निजी भूमि मुआवजा राशि का 95 प्रतिशत है। कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक (केईटी) परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है और अप्रैल 2026 में इसके चालू होने की संभावना है। एलिवेटेड वायाडक्ट के सभी 21 स्पैन पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा सिविल, ट्रैक, सिग्नलिंग और ओवरहेड विद्युतीकरण से जुड़े कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। परियोजना को जल्द ही रेलवे सुरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। नया थानेसर स्टेशन भी अंतिम चरण में है और 10 अप्रैल, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के माध्यम से, सोनीपत से पलवल तक प्रस्तावित ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (ईओआरसी) परियोजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है। फील्ड सर्वे, ड्रोन मैपिंग और यातायात आकलन पूरा कर लिया गया है। संशोधित प्रारूप व्यवहार्यता रिपोर्ट 23 मार्च, 2026 को प्रस्तुत की गई है और वित्तीय विश्लेषण सहित अंतिम रिपोर्ट जल्द आने की संभावना है।

बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) तथा वास्तुकला विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, विशेष सचिव (निगरानी एवं समन्वय) डॉ. प्रियंका सोनी, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव-1 मोहम्मद शाइन तथा एचआरआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री सुखविंदर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त-समाचार

चयनित ग्रुप-डी उम्मीदवारों का होगा बायोमीट्रिक सत्यापन

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयनित कॉमन कैडर ग्रुप-डी के 13,246 कर्मचारियों का बायोमीट्रिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। इन कर्मचारियों का बायोमीट्रिक सत्यापन राज्य के विभिन्न मंडलों में मंडल आयुक्तों तथा पंचकूला में उपायुक्त, पंचकूला के स्तर पर किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंबाला मंडल में 20 अप्रैल, 2026 को 1,451 उम्मीदवारों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इनमें 1,417 कर्मचारी विभिन्न विभागों में तैनात हैं जबकि 34 कर्मचारी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं। करनाल मंडल में 21 अप्रैल, 2026 को कुल 1,662 उम्मीदवारों का सत्यापन किया जाएगा। इनमें से 1,584 कर्मचारी विभागों में कार्यरत हैं जबकि 78 कर्मचारी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं। रोहतक मंडल में 22 और 23 अप्रैल, 2026 को 3,750 उम्मीदवारों का सत्यापन किया जाएगा। इनमें से 3,389 कर्मचारी विभागों में कार्यरत हैं तथा 361 कर्मचारी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं। हिसार मंडल में 24 और 27 अप्रैल, 2026 को 2,918 उम्मीदवारों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इनमें 2,585 कर्मचारी विभागों में कार्यरत हैं जबकि 333 कर्मचारी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं। फरीदाबाद मंडल में 28 अप्रैल, 2026 को 960 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाएगा, जिनमें 954 विभागों में कार्यरत हैं तथा 6 कर्मचारी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं। गुरुग्राम मंडल में 29 अप्रैल, 2026 को 1,841 अभ्यर्थियों का उम्मीदवारों का सत्यापन किया जाएगा, जिनमें 1,801 विभागों में कार्यरत हैं तथा 40 कर्मचारी मंडल आयुक्त कार्यालय से संबद्ध हैं। पंचकूला में 30 अप्रैल, 2026 को 664 अभ्यर्थियों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इनमें चंडीगढ़, पंचकूला तथा विभिन्न विभागों एवं मंडल आयुक्त कार्यालयों से सम्बद्ध शेष अभ्यर्थी शामिल होंगे। सभी मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्त, पंचकूला से अनुरोध किया गया है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बायोमीट्रिक सत्यापन के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक स्टाफ एवं संसाधन उपलब्ध करवाएं। साथ ही सत्यापन के उपरांत उपस्थित, अनुपस्थित तथा सत्यापित उम्मीदवारों की संख्या संबंधी रिपोर्ट भी उपलब्ध करवाने को कहा गया है। सभी विभागाध्यक्षों से भी अनुरोध किया गया है कि वे विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयनित कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों को निर्धारित तिथियों के अनुसार बायोमीट्रिक सत्यापन के लिए भेजना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त विभागवार एवं मंडलवार नोडल अधिकारी नामित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि निर्धारित तिथियों पर कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

अजय कुमार ने संभाला नूंह के उपायुक्त का अतिरिक्त कार्यभार

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के उपायुक्त और श्रीमाता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री अजय कुमार को नूंह के उपायुक्त तथा मेवात विकास एजेंसी, नूंह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। उन्हें यह कार्यभार श्री अखिल पिलानी के अवकाश के चलते सौंपा गया है।

कार्मिशियल गैस का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द करना होगा पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन: विश्राम कुमार मीणा

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि होटल, ढाबा और अन्य संस्थानों को कार्मिशियल गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। जो भी संस्थान पीएनजी के लिए आवेदन करेगा उसी संस्थान को पीएनजी का कनेक्शन लगने तक कार्मिशियल गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए एचपी ऑयल गैस के अधिकारी सर्वे करेंगे अगर सर्वे के दौरान किसी संस्थान के लिए पीएनजी फिलिब्लिटी नहीं बनती तो इस रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित संस्थान को जरूरत के अनुसार कार्मिशियल सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में कुरुक्षेत्र जिले में गैस आपूर्ति की समीक्षा को लेकर अधिकारियों की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नरेश कुमार ने कुरुक्षेत्र जिले की 3 कंपनियों की 27 गैस एजेंसियों की विस्तृत रिपोर्ट हाउस के समक्ष रखी। इसके साथ ही जिला कमेटी के सदस्यों के समक्ष शादी विवाह के लिए कार्मिशियल सिलेंडर की मांग के आवेदनों को रखा। इसके अलावा डीएफएससी ने 29 मार्च की घरेलू गैस सिलेंडरों की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए कहा कि एजेंसियों के पास कुल 12986 सिलेंडर थे, इसमें से 6236 सिलेंडर वितरित किए गए और 6750 सिलेंडरों का स्टॉक एजेंसियों के पास बकाया था। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिले में गैस सिलेंडरों सहित पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं, इसलिए नागरिकों को घबराने या अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा जाए और किसी भी स्तर पर बाधा नहीं आने दी जाए। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे केवल आवश्यकता अनुसार ही गैस की बुकिंग करें और अनावश्यक भंडारण से बचें। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से सब डिविजन के अनुसार सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकने और निरंतर सप्लाई को सुचारू बनाए रखने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों ने अब तक 51 जगहों पर रेड की है और 30 सिलेंडर भी जब्त किए है। इस विभाग की टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय रहकर गैस एजेंसियों पर निगरानी रख रही हैं। प्रतिदिन एजेंसियों से रिपोर्ट ली जा रही है, जिससे आपूर्ति की स्थिति पर सतत नजर बनी हुई है और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी और अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और विवाह जैसे आयोजनों के लिए व्यवसायिक गैस सिलेंडरों की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके लिए संबंधित कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। जमाखोरी करने वालो पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा एलपीजी से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु विभिन्न अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

संपादकीय

अब हर घर होगा ऑनलाइन दर्ज: शुरू हो रही भारत की पहली डिजिटल जनगणना

भारत एक ऐतिहासिक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। बुधवार से शुरू होने जा रही देश की पहली डिजिटल जनगणना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शासन की सोच और कार्यशैली में बड़े परिवर्तन का संकेत है। 8 चुनिंदा स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो रही इस पहल में 33 महत्वपूर्ण सवालों के जरिए देश की सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी स्थिति का विस्तृत आकलन किया जाएगा। यह प्रयोग भविष्य की नीतियों के लिए डेटा-आधारित दृष्टिकोण को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। अब तक भारत में जनगणना पारंपरिक तरीके से होती रही है, जहां गणनाकर्मी घर-घर जाकर कागजी फॉर्म भरते थे। इस प्रक्रिया में समय अधिक लगता था और डेटा के संकलन से लेकर विश्लेषण तक में वर्षों का अंतर आ जाता था। लेकिन डिजिटल जनगणना इस ढांचे को पूरी तरह बदलने जा रही है। मोबाइल ऐप, टैबलेट, क्लाउड-आधारित सिस्टम और रियल-टाइम डेटा एंट्री के जरिए पूरी प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और अधिक सटीक बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बार पूछे जाने वाले 33 सवालों का दायरा भी पहले से कहीं अधिक व्यापक है। यह केवल जनसंख्या की गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छूता है। शिक्षा का स्तर, रोजगार की स्थिति, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का उपयोग, आवास की स्थिति, परिवार की संरचना, प्रवास और सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे विषयों को इसमें शामिल किया गया है। इससे सरकार को न केवल यह पता चलेगा कि देश में कितने लोग हैं, बल्कि यह भी समझ में आएगा कि वे किस तरह का जीवन जी रहे हैं और उनकी वास्तविक जरूरतें क्या हैं। डिजिटल जनगणना का सबसे बड़ा लाभ इसकी गति और सटीकता है। पहले जहां आंकड़े आने में वर्षों लग जाते थे, अब सरकार को लगभग रियल-टाइम में डेटा उपलब्ध हो सकेगा। इससे नीतियों को बनाने और लागू करने में तेजी आएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर कम पाया जाता है, तो वहां तुरंत शैक्षिक योजनाओं को लागू किया जा सकता है। इसी तरह, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी या डिजिटल पहुंच जैसे मुद्दों पर भी तत्काल कदम उठाए जा सकेंगे। हालांकि इस पहल के साथ कई गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा मुद्दा डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का है। जब करोड़ों लोगों की व्यक्तिगत जानकारी डिजिटल रूप में एकत्र की जाएगी, तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होगा। साइबर हमलों और डेटा चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच यह चिंता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि डेटा एन्क्रिप्शन, सुरक्षित सर्वर और कड़े साइबर सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। दूसरी बड़ी चुनौती डिजिटल विभाजन की है। भारत के कई ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट की पहुंच सीमित है और डिजिटल साक्षरता का स्तर भी कम है। ऐसे में वहां सही और पूर्ण डेटा एकत्र करना आसान नहीं होगा। हालांकि सरकार ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन डेटा संग्रह की व्यवस्था और गणनाकर्मियों के विशेष प्रशिक्षण की योजना बनाई है, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन ही इस पहल की सफलता तय करेगा। जनगणना के आंकड़े हमेशा से ही राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। आरक्षण नीति, संसाधनों का वितरण, और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण जैसे कई फैसले इन्हीं आंकड़ों पर आधारित होते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि डेटा पूरी तरह निष्पक्ष और सटीक हो। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या पक्षपात होता है, तो इसका असर दूरगामी हो सकता है और सामाजिक असंतुलन भी पैदा हो सकता है। डिजिटल जनगणना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह भारत को वैश्विक स्तर पर तकनीकी रूप से सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकता है। कई विकसित देशों में पहले से ही डिजिटल डेटा संग्रह की प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है। भारत का यह कदम न केवल उसकी तकनीकी क्षमता को दशार्ता है, बल्कि यह भी बताता है कि देश डेटा-आधारित शासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और स्मार्ट गवर्नेंस जैसी अवधारणाओं को लागू करना और आसान हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की सफलता काफी हद तक इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। गणनाकर्मियों का प्रशिक्षण, तकनीकी ढांचे की मजबूती और नागरिकों की जागरूकता–ये सभी कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि इनमें किसी भी स्तर पर कमी रह जाती है, तो इस महत्वाकांक्षी परियोजना का प्रभाव सीमित हो सकता है। नागरिकों की भागीदारी भी इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। लोगों को यह समझना होगा कि जनगणना केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि यह उनके अपने भविष्य से जुड़ी प्रक्रिया है। सही और सटीक जानकारी देना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी के आधार पर आने वाले वर्षों की नीतियां और योजनाएं तैयार की जाएंगी। अंत में कहा जा सकता है कि भारत की पहली डिजिटल जनगणना एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी पहल है। यह देश को पारंपरिक आंकड़ा संग्रह प्रणाली से निकालकर आधुनिक, तेज और पारदर्शी व्यवस्था की ओर ले जाएगी। हालांकि इसके सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन यदि इन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित किया गया, तो यह पहल भारत के विकास की दिशा को नई गति और स्पष्टता प्रदान कर सकती है। आने वाले वर्षों में यही डेटा देश की नीतियों, योजनाओं और विकास की दिशा तय करेगा–और शायद यही इस पहल की सबसे बड़ी ताकत भी है।

विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनेगा जेवर एयरपोर्ट

मृत्युंजय दीक्षित (हि.स)

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व विकास योजनाओं के लोकार्पण की लहर चल रही है।इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 मार्च को जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) राष्ट्र को समर्पित किया। यह एयरपोर्ट आधुनिकतम सुविधाओं का अद्भुत संगम होगा। यहां से पहली उड़ान उत्तर प्रदेश सरकार के विमान ने भरी, जिसमें प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यात्री बने। इस एयरपोर्ट से चार सप्ताह बाद यात्रियों के लिए नियमित उड़ानें प्रारंभ हो जाएंगी। नोएडा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना का प्रस्ताव 2001 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रखा था किंतु निहित राजनीतिक कारणों से यह अधर में लटका रहा। इस प्रकार इस परियोजना के प्रथम चरण के ही पूर्ण होने में 25 वर्ष लग गए, जिस कारण उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र का विकास भी अटका रहा।

जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट के साथ ही विकसित यूपी और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। यूपी अब देश के सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण के पूर्व ही केंद्र सरकार ने उड़ान 2.0 योजना को मंजूरी प्रदान की है जिसके अंतर्गत 100 नए एयरपोर्ट व 200 नये हेलीपैड बनेंगे जिसके लिए 29,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का सपना है कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा का सुगम आनंद ले सकें और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उड़ान 1.0 योजना में 1.6 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए सबका प्रयास जरूरी है इस परियोजना के लिए किसानों ने भी अपनी जमीन दी है। आधुनिक कनेक्टिविटी का जो विस्तार हो रहा है उसे पश्चिम यूपी में फूड प्रोसेसिंग को बल मिलेगा और यहां के कृषि उत्पाद दुनिया के बाजारों में और बेहतर तरीके से पहुंच सकेंगे।

जेवर एयरपोर्ट की अहम विशेषताएं: जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा तथा प्रथम चरण में ही यह 1.2 करोड़ यात्रियों को एक रन-वे से सेवा प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह देश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा जो सौर ऊर्जा का उपयोग करेगा और कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। इस एयरपोर्ट में आगामी चरणों में 5 रन-वे का निर्माण होने के बाद यात्री क्षमता बढ़कर 22.5 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष हो जाएगी। यह एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से चलेगा।

एयरपोर्ट में आईएलएस कैट-3 सिस्टम है जिससे घने कोहरे में भी विमान आसानी से उतर सकेंगे। इस एयरपोर्ट में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है जिसमें यात्रियों के लिए डिजी लॉकर आधारित बायोमैट्रिक चेक इन फेस स्कैन से प्रवेश और एआई आधारित सुरक्षा होगी। यहां 3900 मीटर लंबा रन-वे होगा जो बड़े विमानों का संचालन कर सकेगा। यह यमुना एक्सप्रेस वे से सीधा जुड़ा है और इसे मेट्रो रेल और प्रस्तावित रैपिड रेल से जोड़ने की योजना है। यहां यात्रियों के लिए प्रवेश से लेकर बोर्डिंग गेट तक पहुंचने की प्रक्रिया बहुत तेज होगी जो लगभग 20 मिनट में पूरी हो सकती है। यहां पर 30 एकड़ में कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण किया गया है जिस पर 800 करोड़ रुपये की लागत आई है तथा 48 चेक इन प्वाइंट बनाए गए हैं। यहां की मल्टीमाइल कार्गो सुविधा की क्षमता आरम्भ में 2.5 लाख मीटिक टन माल की ढुलाई की है, जिसे बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन किया जा सकता है। यहां पर 57 एकड़ में 700 करोड़ की लागत से वेयर हाउस एवं लॉजिस्टिक सुविधा विकसित की गई है। इस एयरपोर्ट के प्रथम चरण के निर्माण में 11200 करोड़ की लागत आई है।

इस एयरपोर्ट के निर्माण व संचालन के बाद दिल्ली-एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश (ग्वालियर - मुरैना), राजस्थान (धौलपर -भरतपुर) के हिस्सों को मिलाकर करीब सात करोड़ आबादी को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। इस एयरपोर्ट के कारण जेवर एयरोट्रोपोलिस सिटी के रूप में चमकेगा। गौतमबुद्ध नगर और आसपास के जिलों के बीच क्षेत्रीय जुड़ाव और विकास होगा। इनके उत्पाद और सेवाओ के समक्ष आने वाली चुनौतियां भी कम होंगी। यह एयरपोर्ट पूर्ण हो जाने के बाद शहर में तमाम होटल व कार्यालय, शापिंग मॉल, लॉजिस्टिक हब आदि का निर्माण भी तीव्र गति से होने जा रहा है। शहर भर में अगली पीढ़ी वाली सुविधाएं विकसित होंगी।

यह एयरपोर्ट केवल रन-वे नहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने का आधार बनेगा। यह एयरपोर्ट प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगा क्योंकि यह उत्तर भारत के विदेश व्यापार व औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का भी सृजन करेगा। यह एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों युवाओं के लिए भी नए अवसर लेकर आने वाला है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

मोदी पर व्यक्तिगत प्रहार टिकेगा नहीं!

विक्रम उपाध्याय (हि.स)

जब पूरी दुनिया अपने अस्तित्व पर चुनौती महसूस कर बचाव के लिए संघर्ष करने में लगी है, तो भारत में अस्तित्वहीन पड़ा विपक्ष अपने लिए इस संकट की घड़ी को सत्ता में लौटने का एक अवसर मान रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग में जब हर देश में राजनीतिक रूप से पक्ष विपक्ष एक टेबल पर बैठ कर चुनौतियों से पार पाने का दम भर रहा है, तो भारत में विपक्ष और विरोधियों की ओर से सरकार के मुखिया पर सबसे भीषण प्रहार किया जा रहा है, केवल नीतिगत ही नहीं, व्यतिगत रूप से भी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरिमा और विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

एक तरफ उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री ठहराने का एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है, तो दूसरी तरफ उनके व्यक्तित्व और आचरण को ही तार-तार करने का षड्यंत्र रचा रहा है। वैसे ही जैसे 2013 में कोबरापोस्ट और गुलेल द्वारा किसी नारी की निजता भंग करने के आरोप के सहारे मोदी की छवि बिगाड़ने का एक प्रयास किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बिना विचलित हुए ईरान और अरब दोनों के साथ अद्भुत सामंजस्य बिठाते हुए, केवल भारतीयों की सुरक्षा और देश की ऊर्जा संरक्षता के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं।

विपक्ष के कुछ बड़े नेता पहले भी कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ निजता भंग करने के आरोप लगाते रहे हैं, उनमें ही एक आरोप प्रयास पेगासस स्पाइवेयर के इस्तेमाल के जरिए जासूसी करने का भी रहा, मामला उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) तक गया। वहां विरोधियों की दाल नहीं गली, और वे झटका खा कर लौट आए। वर्तमान सरकार के मुखिया विपक्ष के नेताओं से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यह बात आम लोगों को भी हास्यास्पद लगी।

विपक्ष में इस समय कोई ऐसा नेता नहीं है, जो प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत छवि पर दाग लगाने और जनता में उसकी विश्वसनीयता स्थापित करने का माद्दा रखता है। कारण केवल यह नहीं कि विपक्ष के किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं है एक राजनीतिज्ञ के नाते नरेन्द्र मोदी द्वारा स्थापित अपने सार्वजनिक जीवन के मानदंड पर उंगली उठा सके, बल्कि मोदी की जीवनशैली ऐसी रही है, कि वहां किसी तरह की कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं बनती है।

मोदी जब सत्ता की राजनीति के नायक बने तब उम्र की 50 वीं दहलीज पार कर चुके थे। उसके पहले वे या तो संघ के काम में देश भर के संघ कार्यालयों में रहे या फिर भाजपा की व्यवस्था में। निजी जिंदगी और निजता के संरक्षण का कोई विकल्प भी अपने लिए नहीं चुना। मीडिया में भी सुब्रमण्यम स्वामी को छोड़कर किसी और राजनीतिज्ञ ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अनर्गल टिप्पणी नहीं की। स्वामी ने तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी कई ऐसी टिप्पणियां की हैं और इसके कारण ही उन्होंने एक गंभीर राजनेता की पहचान खो दी है।

प्रधानमंत्री मोदी लगभग 25 वर्षों से विपक्ष के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। काम के मामले में कोई उन्हें चुनौती दे नहीं पा रहा है। राजनीति के मैदान में वे विपक्ष की पकड़ से बहुत आगे निकल गए हैं। इसीलिए विरोधी राजनतिक पार्टियां जनता में मोदी के प्रति बनी धारणा को ही कमजोर करने की जरूरत शिद्दत के साथ महसूस कर रही हैं। कांग्रेस का नेतृत्व चुनावी मुकाबले में कमजोर और अक्षम सिद्ध हो चुका है। प्रधानमंत्री के साथ विकास के मुद्दे पर कांग्रेस बहस से भी बचती है। जनता से किये हर वादे पर भी मोदी खरे उतरते हैं। हर भारतीय को मोदी सरकार के कारण अपने अपने जीवन में कोई ठोस सुधार दिखाई देता है। 12 साल के केंद्र में शासन में किसी भ्रष्टाचार या घोटाला का नाम तक नहीं आया। इसलिए ही मोदी की व्यक्तिगत छवि पर लगातार हमले की रणनीति पर विपक्ष अब काम कर रहा है और मोदी के जीवन के कुछ पहलुओं को बुरा दिखाने का प्रयास कर रहा है, ताकि लोगों के मन में कुछ सवाल पैदा कर सके। पर वे शायद भूल रहे हैं कि उनके इस बचकाने रवैये से उनकी थोड़ी-बहुत साख जो बची है उसे भी गंवा बैठेंगे।

कांग्रेस के रणनीतिकारों ने देश-विदेश के अपने सलाहकारों से मंत्रणा करने के बाद शायद यह तय कर लिया है कि मोदी को कमजोर करने के लिए एंटी परसेप्शन मैनेजमेंट पर ही सारा जोर देना होगा और सोशल मीडिया के जरिए उनकी व्यक्तिगत छवि पर आघात करना होगा। कांग्रेस के लिए यह रणनीति कितना काम करेगी यह तो आने वाला ही समय बताएगा, लेकिन ग्रामीण मतदाताओं के बीच इस मुकाबले को ले जाने की चुनौती बहुत बड़ी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीणों को आर्थिक सहायता देने के मामले में कांग्रेस से बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया है और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इसी से सबसे ज्यादा स्थापित भी हुई है। वहां भाजपा की छवि धूमिल करना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी।

कांग्रेस के अपने पास मोदी पर व्यक्तिगत लांछन लगाने वाले विश्वसनीय चेहरे भी नहीं हैं, क्योंकि महिलाओं के प्रति कांग्रेस नेताओं के दुर्व्यवहार और जहरीले बोल की एक लंबी फेहरिस्त है। पीछे की छोड़िए वर्तमान के ही कई कांग्रेसी नेता महिलाओं के मान मर्दन के आरोपी हैं। नाम लीजिए राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला का, उन्होंने भाजपा सांसद हेमा मालिनी के राजनीतिक योगदान पर अभद्र टिप्पणी की थी। नाम लीजिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का, उन्होंने 2024 के आम चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत का भाव पूछ लिया था। कर्नाटक के एक कांग्रेस नेता ने महिलाओं को घर पर खाना बनाने तक ही रखने की सलाह दे डाली थी। बंगाल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भी नहीं बख्शा, उन्हें राष्ट्रपत्नी बना डाला। कांग्रेस की एक पूर्व नेता चेरियन फिलिप ने तो यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस के टिकट यौन लाभ के बदले भी दिए जाते थे।

अब मधु किश्वर के सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक सनसनी रिपोर्ट प्रकाशित किये जाने पर विपक्ष के नेता फूले नहीं समा रहे हैं। कांग्रेस महिला मोर्चा की नेता अलका लांबा हों या तृणमूल कांग्रेस की मोईया मित्रा सबने अपने-अपने तरीके से मोदी के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब मीडिया वाले ही बता रहे हैं कि मधु किश्वर पहले भी कई गलत या भ्रामक पोस्ट कर चुकी हैं। जाहिर है कांग्रेस का उद्देश्य बिना किसी पूर्ण शोध के जंगल की आग की तरह भ्रम फैलाना है। कांग्रेस पहले भी ब्लैक लाइव्स मैटर की तरह देश में जाति आधारित आंदोलन को, काले कानून के नाम पर किसानों के आंदोलन को और कोविड के दौरान एंटी-लॉकडाउन प्रोटेस्ट को हवा देकर प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर करने की कोशिश कर चुकी है। यह बात अलग है कि इसमें वह विफल रही।

दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के अनुशासन की कायल है। उनके बारे में यह लोगों को पता है कि वे शायद अकेले नेता हैं जो खरी-खरी कहने और किसी की भी अक्षमता पर उसकी आलोचना करने से नहीं हिचकते। उनका सीधा सिद्धांत है - काम करो नहीं तो बाहर निकलो। वे समय के बहुत पाबंद और बहुत व्यवस्थित नेता हैं। उनमें औरों की तरह अमीर बनने का जुनून नहीं है। वह मीडिया को भी खुश करने की कोशिश नहीं करते। वह बहुत कम लोगों पर भरोसा करते हैं। उनके करीबी साथियों की भी संख्या कम है। इसलिए उनके राजदार भी कम है। उनकी मां के अलावा उनके किसी दोस्त या रिश्तेदार को प्रधानमंत्री आवास में नहीं देखा गया, इसलिए मोदी पर व्यक्तिगत लांछन लगाना और उसे सिद्ध करना संभव नहीं है।

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

आज का राशिफल

मेष: आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और आप अपने कार्यों को पूरे समर्पण के साथ करेंगे। प्रेम संबंधों में निष्ठा बनी रहेगी। सामाजिक कार्यों और परोपकार में रुचि बढ़ सकती है, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी। किसी उपलब्धि के लिए सम्मान मिलने के संकेत हैं। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: आज नियम-कानूनों का पालन बेहद जरूरी है, खासकर सरकारी मामलों में। अनावश्यक यात्राओं से बचना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। दूसरों के मामलों में दखल न दें। खांसी या बुखार जैसी परेशानी भी संभव है। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। साझेदारी में काम करते समय सतर्क रहें। किसी बड़ी समस्या का समाधान मिलने से राहत मिलेगी। मित्रों से मिलने या निमंत्रण का योग है। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: आज नए कार्य शुरू करने से बचें। शारीरिक चोट, विशेषकर पैरों में, का खतरा है। काम का दबाव बढ़ सकता है और ओवरटाइम करना पड़ सकता है। आलस्य से दूर रहें। नकारात्मक लोगों से सावधान रहें और वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें। *(सिटी दर्पण)*

सिंह: करियर में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं और उच्च पद प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बच्चों से सुखद समाचार मिल सकता है। व्यापार में अच्छा लाभ होने की संभावना है। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाने में आप सफल रहेंगे। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है और रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे। आप अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी। *(सिटी दर्पण)*

तुला: आज आप एक साथ कई कार्यों को संभालने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से चल रही समस्याओं में सुधार होगा। प्रभावशाली लोगों से संपर्क मजबूत होंगे। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और विरोधियों से समझौते के संकेत हैं। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित होगा। लोग आपके व्यवहार को गलत समझ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खानपान पर ध्यान दें। पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं और मानसिक तनाव बना रह सकता है। *(सिटी दर्पण)*

धनु: दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार के सिलसिले में यात्रा संभव है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। सोशल मीडिया पर आपकी सक्रियता बढ़ सकती है। नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि के संकेत हैं और संतान की प्रगति से खुशी मिलेगी। *(सिटी दर्पण)*

मकर: आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक सजग रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, विशेषकर डायबिटीज के मरीज। कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। जरूरतमंदों की सहायता करने का अवसर मिलेगा। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं दूर होंगी। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: आप अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करेंगे। तकनीकी शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। भावनात्मक रूप से आप मजबूत रहेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को लाभकारी समाचार मिल सकते हैं। मित्रों के साथ समय आनंददायक रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

मीन: निवेश करते समय सावधानी बरतें। करीबी लोग व्यवहार में बदलाव दिखा सकते हैं, जिससे मन विचलित हो सकता है। अधिकारों को लेकर चिंता बनी रह सकती है। कार्यस्थल पर सहकर्मी असंतुष्ट दिख सकते हैं। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें और लेन-देन में सतर्कता रखें। *(सिटी दर्पण)*

हिंसा से व्याकुल दुनिया को महावीर का मार्गदर्शन

योगेश कुमार गोयल (हि.स)

'अहिंसा परमो धर्मः' का उद्घोष करने वाले भगवान महावीर का जीवन और दर्शन केवल एक धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है बल्कि यह सम्पूर्ण मानवता के लिए शाश्वत मार्गदर्शक सिद्धांतों का स्रोत है। आज का युग विज्ञान, तकनीक और भौतिक उपलब्धियों के शिखर पर अवश्य पहुंच गया है लेकिन इसके साथ ही मानवता नैतिक, मानसिक और पर्यावरणीय संकटों से भी जूझ रही है। ऐसे समय में भगवान महावीर के उपदेश और अमृतवाणी पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो उठती है। आधुनिक जीवन की आपाधापी में मनुष्य अपने स्वार्थ, लोभ और अहंकार के वशीभूत होकर ऐसे निर्णय लेने लगा है, जो न केवल उसके अपने जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि समाज और प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ देते हैं। हिंसा आज केवल शारीरिक रूप तक सीमित नहीं रही बल्कि विचारों, शब्दों और व्यवहार में भी व्याप्त हो चुकी है। प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में व्यक्ति संवेदनहीन होता जा रहा है। ऐसे परिदृश्य में महावीर स्वामी का अहिंसा दर्शन मानवता को करुणा, सहिष्णुता और आत्मसंयम की ओर लौटने का आह्वान करता है।

भगवान महावीर का दर्शन इस मूल विचार पर आधारित है कि संसार का प्रत्येक जीव समान है और सभी में आत्मा का वास है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी भी जीव को पीड़ा देना स्वयं अपने अस्तित्व को आहत करना है। आज जब पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के विनाश जैसी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं, तब महावीर का यह सिद्धांत अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है कि पेड़-पौधे, जल, वायु और अग्नि भी चेतन तत्व हैं और उनके प्रति भी संवेदनशीलता आवश्यक है। महावीर स्वामी ने केवल उपदेश ही नहीं दिए बल्कि अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि संयम, तप और आत्मानुशासन के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर कर सकता है। उन्होंने कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। कर्म ही जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं और उसी के अनुसार जीव विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है। यह विचार आज के समय में व्यक्ति को अपने आचरण के प्रति सजग और जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देता है।

उनकी अमृतवाणी में जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन निहित है। वे कहते हैं कि संसार के सभी प्राणी बराबर हैं, इसलिए 'जीओ और जीने दो' का सिद्धांत अपनाना चाहिए। यह केवल एक नैतिक उपदेश नहीं बल्कि सामाजिक सद्भाव और शांति का आधार है। यदि समाज में हर व्यक्ति इस सिद्धांत को आत्मसात कर ले तो हिंसा, द्वेष और संघर्ष स्वतः समाप्त हो सकते हैं। महावीर स्वामी ने यह भी कहा कि अहिंसा से बड़ा कोई व्रत नहीं है। आज जब युद्ध, आतंकवाद और सामाजिक हिंसा विश्व के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त हैं, तब यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति स्वयं हिंसा करता है, दूसरों से करवाता है या हिंसा का समर्थन करता है, वह अपने लिए शत्रुता और दुःख का बीज बोता है। यह विचार आधुनिक समाज में नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करता है।

उनका धर्म केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं था बल्कि आंतरिक शुद्धता पर आधारित था। उन्होंने कहा कि धर्म का स्थान आत्मा की पवित्रता में है, बाहरी आडंबर उसमें सहायक तो हो सकते हैं परंतु अनिवार्य नहीं। यह विचार आज के समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब धर्म का स्वरूप कई बार बाहरी प्रदर्शन तक सीमित हो जाता है। महावीर का संदेश हमें सच्चे धर्म की ओर लौटने का मार्ग दिखाता है, जहां आत्मा की शुद्धता और आचरण की पवित्रता ही सर्वोपरि है। महावीर स्वामी ने मानव मन के चार प्रमुख दोषों (क्रोध, मान, माया और लोभ) को जीवन के पतन का कारण बताया। उन्होंने कहा कि क्रोध प्रेम को नष्ट करता है, अहंकार ज्ञान को, छल मित्रता को और लोभ सभी गुणों को समाप्त कर देता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में यह शिक्षाएं अत्यंत उपयोगी हैं। यदि व्यक्ति इन दोषों पर नियंत्रण कर ले तो उसका जीवन संतुलित और सुखमय बन सकता है।

उनकी वाणी में सामाजिक समानता का भी स्पष्ट संदेश मिलता है। उन्होंने कहा कि जन्म से नहीं बल्कि कर्म से व्यक्ति महान बनता है। यह विचार सामाजिक न्याय और समानता की भावना को मजबूत करता है। आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में भी यह सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक है। महावीर स्वामी ने सेवा को सर्वोच्च धर्म बताया। उन्होंने कहा कि रोगियों और पीड़ितों की सेवा करना प्रभु की सेवा से भी बढ़कर है। आज जब समाज में संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है, तब यह संदेश मानवता को पुनः जागृत करने का कार्य करता है। कोरोना महामारी जैसे संकटों के दौरान हमने देखा कि सेवा और सहानुभूति ही समाज को संभालने का सबसे बड़ा आधार बनी। उनकी शिक्षाओं में स्त्री-पुरुष समानता का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुक्ति पाने का अधिकार सभी को समान रूप से है। यह विचार आज के समय में लैंगिक समानता के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महावीर स्वामी का दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि धैर्य और सहनशीलता के बिना अहिंसा का पालन संभव नहीं है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य खो देता है, वह सच्चे अर्थों में अहिंसक नहीं हो सकता। यह शिक्षा आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में मानसिक संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। उनकी अमृतवाणी का सार यह है कि मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाया जाए। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन की सर्वोच्च साधना है। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है। यह विचार व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सहायता करता है।

आज के समय में, जब मानवता अनेक चुनौतियों से जूझ रही है, चाहे वह नैतिक पतन हो, पर्यावरणीय संकट हो या मानसिक अशांति, भगवान महावीर की शिक्षाएं एक प्रकाश स्तंभ की तरह मार्गदर्शन करती हैं। उनका दर्शन न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुधारने का मार्ग दिखाता है बल्कि समाज और विश्व में शांति, सद्भाव और संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा भी देता है। महावीर जयंती केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आत्ममंथन और आत्मसुधार का अवसर है। यह हमें अपने भीतर झांकने और यह विचार करने का अवसर देती है कि क्या हम वास्तव में अहिंसा, सत्य, संयम और करुणा के मार्ग पर चल रहे हैं।

यदि हम भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन सार्थक होगा बल्कि समाज और विश्व भी अधिक शांतिपूर्ण और मानवीय बन सकेगा। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवान महावीर की अमृतवाणी सदैव प्रासंगिक रहेगी। यह मानवता के लिए एक ऐसी अमूल्य धरोहर है, जो समय, परिस्थिति और युग की सीमाओं से परे जाकर हर युग में मार्गदर्शन करती रहेगी।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

पंजाब के हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर छिपाने का खुलासा

भगवंत मान सरकार द्वारा जांच का दायरा बढ़ाने से हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में टर्नओवर छिपाने का मामला 500 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमानः हरपाल सिंह चीमा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां पंजाब के हॉस्पिटैलिटी (खाद्य एवं पेय व्यवसाय) क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर छिपाने के एक बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए ढाबों, खाने-पीने के स्थानों, रेस्टोरेंट्स और फास्ट-फूड आउटलेट्स में गहरी जड़ें जमा चुकी और व्यवस्थित तरीके से आय कम दिखाने की प्रवृत्ति का पदार्फाश किया। वित्त मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने सार्वजनिक राजस्व की सुरक्षा के लिए तकनीक-आधारित सख्त कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत 882 संस्थानों को जांच के घेरे में लिया गया और अब तक 2.02 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और अधिक डेटा के विश्लेषण से टर्नओवर छिपाने का यह मामला लगभग 500 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

इस बात का उल्लेख करते हुए कि मोहाली, जालंधर और लुधियाना जैसे प्रमुख शहरी केंद्र टैक्स चोरी के मुख्य गढ़ के रूप में उभरे हैं, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा कि अधिक नकदी और हाइब्रिड भुगतान (नकद और डिजिटल दोनों) वाले क्षेत्र इस धोखाधड़ी के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा कि एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स, टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट और स्टेट इंटेलिजेंस एवं प्रिवेंटिव यूनिट (सिपू) से प्राप्त जानकारी तथा बिल लाओ, इनाम पाओ योजना की सफलता के आधार पर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए तकनीक का पूरा उपयोग सुनिश्चित करते हुए हर उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, होटल, ढाबे, खाने-पीने के स्थान, बेकरी, मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट्स, कैटरिंग सेवाएं और ऐसे अन्य संस्थानों को कवर करने वाले एक व्यापक, राज्य स्तरीय और डेटा-आधारित अभियान के माध्यम से हमने वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित कुल

- 882 संस्थान जांच के घेरे में, भगवंत मान सरकार द्वारा सख्ती से अब तक 2.02 करोड़ रुपये की वसूलीः हरपाल सिंह चीमा
- ढाबों से लेकर रेस्टोरेंट्स तक, बड़े कर अभियान के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में आय कम दिखाने का खुलासाः हरपाल सिंह चीमा

882 संस्थानों की पहचान की है।

वित्त मंत्री ने आगे कहा, अधिक विश्लेषण और वित्त वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 से संबंधित डेटा को शामिल करने के साथ टर्नओवर छिपाने का कुल आकार लगभग 500 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है।

चल रही जांच के परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, अब तक की गई प्रारंभिक जांच में 239 मामलों की जांच की गई है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 50 करोड़ रुपये के टर्नओवर छिपाने का पता चला है। उन्होंने आगे कहा, इसमें 5 प्रतिशत की दर से 2.54 करोड़ रुपये का टैक्स शामिल है और हमारे विभाग ने अब तक 2.02 करोड़ रुपये की वसूली सुनिश्चित की है, जबकि शेष वसूली की प्रक्रिया जारी है।

इन अनियमितताओं के स्तर को उजागर करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, हमने 3 करदाताओं द्वारा 2 करोड़ रुपये से अधिक, 6 द्वारा 1 करोड़ रुपये से अधिक, 18 द्वारा 50 लाख रुपये से अधिक, 26 करदाताओं द्वारा 25 लाख रुपये से अधिक और 91 करदाताओं द्वारा 5 लाख रुपये से अधिक का टर्नओवर छिपाने का पता लगाया है।

क्षेत्र-विशेष रुझानों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, हमारे आगे के विश्लेषण से यह सामने आया है कि अधिक नकदी और हाइब्रिड भुगतान वाले क्षेत्रों में व्यवस्थित रूप से आय कम दिखाने का पैटर्न मौजूद है। उन्होंने आगे कहा, आय छिपाने में ढाबों का हिस्सा लगभग 10 करोड़ रुपये है, इसके बाद छोटे खाने-पीने के स्थानों, कॉफी और चाय बार का हिस्सा लगभग 8 करोड़ रुपये और पिज्जा एवं फास्ट-फूड आउटलेट्स का हिस्सा 6 करोड़ रुपये से अधिक है।

जिलावार विवरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, मोहाली में सबसे अधिक 8.16 करोड़ रुपये के टर्नओवर छिपाने का मामला सामने आया है, इसके बाद जालंधर में 6.72 करोड़ रुपये और लुधियाना में 5.48 करोड़ रुपये सामने आए हैं, जो कि पकड़ी गई टैक्स चोरी में मुख्य योगदान देने वाले जिले हैं। उन्होंने आगे कहा कि पटियाला और अमृतसर में तुलनात्मक रूप से कम अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनमें क्रमशः 3.83 करोड़ रुपये और 0.99 करोड़ रुपये की चोरी पकड़ी गई है।

इस कार्रवाई के पीछे अपनाई गई कार्यप्रणाली की व्याख्या करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंटिव यूनिट द्वारा व्यावसायिक डेटा की गहन जांच के दौरान यह पाया गया कि ऐसे संस्थानों की बड़ी संख्या ऑनलाइन बिलिंग एप्लिकेशन का उपयोग कर रही थी। उन्होंने आगे कहा, मैं टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंटिव यूनिट तथा हमारी 'बिल लाओ, इनाम पाओ' योजना की शानदार सफलता को इस बड़े स्तर की टैक्स चोरी पकड़ने का पूरा श्रेय देता हूं।

उन्होंने आगे विस्तार से कहा, जोखिम मानकों, डेटा एनालिटिक्स और जीएसटी रिटर्न के साथ तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर हमने टर्नओवर छिपाने की संभावित घटनाओं की पहचान की। हमने संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लेन-देन का विस्तृत डेटा प्रदान करने के निर्देश दिए, जिसका उपयोग अब फील्ड टीमें जमीनी जांच और रिटर्न के मिलान के लिए कर रही हैं। संतुलित कार्रवाई पर जोर देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, यह ध्यान देने योग्य है कि 52 संस्थानों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई, जो डेटा-आधारित चयन पर आधारित संतुलित प्रवर्तन और जांच को दर्शाता है।

आगे की कार्रवाई की रूपरेखा बताते हुए उन्होंने कहा, शेष मामलों की सक्रिय रूप से जांच और गहन पड़ताल की जा रही है और उम्मीद है कि जांच एवं वसूली की पूरी प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने आगे कहा, जांच को और मजबूत करने के लिए विभाग यूपीआई लेन-देन और अन्य डिजिटल भुगतान के रिकॉर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, जिससे रिपोर्ट किए गए टर्नओवर और वास्तविक प्राप्तियों के बीच गहन मिलान संभव होगा और टैक्स चोरी पकड़ने की सटीकता बढ़ेगी।

उल्लंघन करने वालों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, भगवंत मान सरकार कर अनुपालन सुनिश्चित करने और राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए तकनीक, डेटा एनालिटिक्स और समन्वित फील्ड प्रवर्तन का पूरा उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा, कर चोरी के सभी मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि कर नियमों का पालन करने वाले करदाताओं को सुविधाएं मिलती रहेंगी।

दिव्यांग व्यक्तियों और आंगनवाड़ी कार्यकताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्धः डॉ. बलजीत कौर

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहां अन्य वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, वहीं दिव्यांग व्यक्तियों तथा आंगनवाड़ी कार्यकताओं और हेल्परों के कल्याण के लिए भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार दिव्यांग व्यक्तियों, आंगनवाड़ी कार्यकताओं और हेल्परों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका शीघ्र और प्रभावी समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

पंजाब भवन, चंडीगढ़ में दिव्यांग यूनियनों तथा आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की यूनियनों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि ये दोनों वर्ग राज्य के सामाजिक कल्याण ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं, वहीं दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण और सशक्तिकरण भी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है।

मंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान यूनियनों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया और विभाग तथा यूनियनों के बीच सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जिन मांगों का समाधान विभागीय स्तर पर संभव है, उन्हें तुरंत निपटाया जाएगा, जबकि अन्य मुद्दों को सरकार स्तर पर उठाकर जल्द समाधान किया जाएगा। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार जन-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ कल्याणकारी वर्गों की जायज मांगों को हल करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आंगनवाड़ी कार्यकताओं, हेल्परों और दिव्यांग व्यक्तियों की जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और उनके कल्याण के लिए और ठोस कदम उठाए जाएंगे।

इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री गुरकीरत कृपाल सिंह, निदेशक श्रीमती शेना अग्रवाल, डिप्टी डायरेक्टरों सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्यसभा सांसद व ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस -राजिंदर गुप्ता अमेरिका में उपचाराधीन, तीसरी हार्ट सर्जरी प्रस्तावित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

राज्यसभा सांसद और ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस राजिंदर गुप्ता इन दिनों अमेरिका में उपचाराधीन हैं और जल्द ही उनकी तीसरी बड़ी हार्ट सर्जरी होने की संभावना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजिंदर गुप्ता नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए अमेरिका के प्रसिद्ध क्लीवलैंड क्लिनिक गए थे। जांच के दौरान डॉक्टरों ने उनकी स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद नई कार्डियक प्रक्रिया की सलाह दी है।

सूत्रों के मुताबिक, यह सर्जरी इसी सप्ताह होने की संभावना है। सर्जरी के बाद गुप्ता कुछ समय तक अमेरिका में ही चिकित्सकीय निगरानी में रहेंगे। उनकी रिकवरी अवधि करीब तीन सप्ताह बताई जा रही है, जिसमें अस्पताल में भर्ती रहना भी शामिल है।

इस महत्वपूर्ण समय में उनका परिवार—पत्नी, बेटा और बेटी—उनके साथ मौजूद है। वहीं, भारतीय दूतावास का कार्यालय भी लगातार परिवार के संपर्क में है और हर संभव सहयोग प्रदान कर रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी राजिंदर गुप्ता वर्ष 2002 और 2009 में हृदय सर्जरी करा चुके हैं।

संक्षिप्त-समाचार

पंजाब के राज्यपाल द्वारा महावीर जयंती पर बधाई

चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने महावीर जयंती के पावन अवसर पर पंजाब एवं चंडीगढ़ के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री कटारिया ने कहा कि भगवान महावीर अहिंसा, शांति और सद्भाव के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा, सार्वभौमिक भाईचारा, करुणा और त्याग के मूल्यों को न केवल प्रचारित किया बल्कि उन्हें स्वयं आचरण में उतारा। भगवान महावीर द्वारा बताए गए ये महान सिद्धांत हमारी समावेशी संस्कृति का प्रतिबिंब हैं और आज भी हमें धार्मिक, नैतिक और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि यह पावन अवसर सभी समुदायों द्वारा मिल-जुलकर मनाया जाएगा और सभी में आपसी भाईचारे को और अधिक सुदृढ़ करने व मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने का नया संकल्प जगेगा।

भगवान अयप्पन की भक्ति और उत्साह के साथ भव्य शोभायात्रा आयोजित

चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सेक्टर 31ऊमें स्थित श्री कार्तिकेय स्वामी मंदिर और सेक्टर 47 उ में स्थित श्री अयप्पा मंदिर के वार्षिक अनुष्ठानों के सिलसिले में, आज भगवान अयप्पन की एक भव्य और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण शोभायात्रा अत्यंत भक्ति और उत्साह के साथ आयोजित की गई। इस अनूठी और सदियों पुरानी परंपरा के एक हिस्से के रूप में, यह शोभायात्रा पूरे विधि-विधान के साथ भगवान कार्तिकेयन मंदिर गई और उसके बाद अयप्पा मंदिर लौट आई। यह अनुष्ठान भगवान अयप्पन और भगवान कार्तिकेयन के बीच के दिव्य भाईचारे का प्रतीक है, जिन्हें हिंदू परंपरा में भाई के रूप में पूजा जाता है। यह पवित्र प्रथा चंडीगढ़ में रहने वाले मलयालम और तमिल समुदायों के बीच सांस्कृतिक एकीकरण और एकता का भी एक सशक्त प्रतिनिधित्व करती है। यह आयोजन भक्तों के बीच आपसी सम्मान, सद्भाव और साझा आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है। विशेष रूप से, यह सार्थक परंपरा पिछले 30 वर्षों से बिना किसी रुकावट के जारी है; हर बीतते वर्ष के साथ यह और अधिक सुदृढ़ होती जा रही है और इसमें विभिन्न समुदायों के भक्तों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। इस वर्ष के उत्सव में भक्तों, समुदाय के सदस्यों और मंदिर के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। जिससे एकता, भक्ति और भाईचारे की भावना और अधिक बलवती हुई। आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और ऐसी परंपराओं को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, जो सांस्कृतिक बंधनों और सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करती हैं।

इमेजिन ने चंडीगढ़ में बाइक रैली का आयोजन किया

चंडीगढ़। चंडीगढ़ में खुले उत्तर भारत के सबसे बडे इमेजिन स्टोर के शानदार लॉन्च का जश्न एक जोरदार बाइक रैली के साथ मनाया। इस रैली में पूरे क्षेत्र से टेक्नोलॉजी के शौकीन, बाइकर्स और एप्पल के फैंस एक साथ शामिल हुए। यह आयोजन जुनून, समुदाय और इनोवेशन के उस बेहतरीन मेल का प्रतीक था, जो इमेजिन के अनुभव की पहचान है। जुनून से प्रेरित, इनोवेशन से संचालित थीम वाली इस रैली में 150 बाइकर्स का एक शानदार काफिला शहर के मुख्य रास्तों से गुजरा, जिससे स्टोर के खुलने को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह और उत्सुकता पैदा हुई। यह पहल इमेजिन की अपने समुदाय के साथ गतिशील और सार्थक तरीकों से जुड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही यह एप्पल की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की भावना का भी जश्न मनाती है। चंडीगढ़ में हाल ही में लॉन्च किया गया यह नया स्टोर ग्राहकों को एप्पल का एक बेहतरीन अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज के साथ-साथ विशेषज्ञों की सलाह, व्यक्तिगत सेवाएँ और प्रोडक्ट्स के सीधे इस्तेमाल अनुभव भी उपलब्ध है। इस स्टोर का उद्देश्य पूरे क्षेत्र के ग्राहकों के लिए रचनात्मकता, सीखने और इनोवेशन का एक केंद्र बनना है। इस अवसर पर बोलते ट्रेजर के एमडी और सीईओ शौर्य सेठ ने कहा कि यह बाइक रैली सिर्फ.हमारे नए स्टोर का जश्न नहीं है बल्कि यह इनोवेशन के प्रति हमारे जुनून और समुदाय के साथ हमारे जुड़ाव का भी प्रतीक है। चंडीगढ़ एक जीवंत शहर है, और हम यहाँ अपने ग्राहकों के लिए विश्व-स्तरीय एप्पल अनुभव को और भी करीब लाने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। इस लॉन्च कार्यक्रम में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और समुदाय का जबरदस्त समर्थन मिला। इससे उत्तरी भारत में बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के प्रति इमेजिन के निरंतर विस्तार और प्रतिबद्धता के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।

गैंगस्टरों ते वार का 69वां दिनः पंजाब पुलिस द्वारा 455 स्थानों पर छापेमारी; 162 गिरफ्तार

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के निदेशों के तहत शुरू की गई निर्णायक गैंगस्टरों ते वार मुहिम के 69वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों के चिन्हित और मैप किए गए 455 ठिकानों पर छापेमारी की।उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरों ते वार पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाया जा रहा एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरूआत 20 जनवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब श्री गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष अभियान चला रही हैं। 69वें दिन पुलिस टीमों ने 162 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 1 हथियार बरामद किया, जिससे इस अभियान की शुरूआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 17,836 हो गई है। इसके अलावा 54 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 107 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 4 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचना भी साझा कर सकते हैं। इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपने अभियान युद्ध नशों विरुद्ध को 394वें दिन भी जारी रखते हुए आज 91 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 837 ग्राम हेरोइन, 2.6 किलोग्राम अफीम, 198 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 2500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही केवल 394 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 56,193 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 24 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित भी किया है।

- पुलिस टीमों ने 54 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की, 107 को पूछताछ के बाद रिहा किया

पंजाब राज्य सैनिक बोर्ड की 35वीं बैठक राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में आयोजित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब राज्य सैनिक बोर्ड की 35वीं बैठक आज पंजाब लोक भवन में गुलाब चंद कटारिया, माननीय राज्यपाल पंजाब की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग तथा पंजाब राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा शहीदों के परिवारों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने इन योजनाओं के प्रभावी एवं सुचारु क्रियान्वयन पर बल दिया, ताकि लाभार्थियों को समुचित सहायता सुनिश्चित की जा सके।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत बोर्ड ने 7 मार्च, 2025 को आयोजित पिछली बैठक में अनुमोदित एजेंडा बिंदुओं की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026ञ्27 हेतु फ्लैग डे फंड से संचालित किए जाने वाले कुछ नए कल्याणकारी प्रावधानों को भी मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं:

दिवंगत पूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए 10,000 की अतिरिक्त अंतिम संस्कार सहायता राशि

सेवा के दौरान निधन होने वाले अग्निवीरों के निकटतम परिजनों के लिए जीवन निर्वाह भत्ता

पंजाब अमलगमेटेड फंड से पूर्व सैनिकों के मेधावी बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना, जिससे उन्हें उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके

बोर्ड ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2025ञ्26 एवं 2026ञ्27 के लिए आवश्यक बजट आवंटन को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक के दौरान राज्यपाल ने सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, विधवाओं एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु प्रयासों को और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के वीर सैनिक सदैव देश की सीमाओं की रक्षा में अग्रिम पंक्ति में रहे हैं और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अनेक बलिदान दिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन वीर सैनिकों के परिवारों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना हमारा कर्तव्य है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

राज्यपाल ने शहीदों के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा वीर नारियों के लिए महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया।

इस बैठक में मोहिंदर भगत, माननीय मंत्री (रक्षा सेवाएं कल्याण), श्री जे.एम. बालामुरुगन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, रक्षा सेवाएं कल्याण पंजाब; ब्रिगेडियर भूपिंदर सिंह ढिल्लों (सेवानिवृत्त), निदेशक, रक्षा सेवाएं कल्याण पंजाब; तथा मुख्यालय वेस्टर्न कमांड, केन्द्रिय सैनिक बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी एवं पंजाब राज्य सैनिक बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

राज्य की मंडियों में बाहरी राज्यों से गेहूं की बिक्री रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएः लाल चंद कटारूचक

कल से शुरू होने वाले गेहूं खरीद सीजन के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की तैयारियां पूरी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों (डीएफएससी) को राज्य की मंडियों में बाहरी राज्यों से गेहूं की बिक्री पर कड़ी नजर रखने के निर्देश देते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक ने विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में सख्त निगरानी रखने को कहा है।

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल से शुरू हो रहे गेहूं खरीद सीजन को बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न कराने के संकल्प को दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री ने डीएफएससी को व्यक्तिगत रूप से मंडियों का दौरा कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि खरीद सीजन के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। डीएफएससी और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में आगामी खरीद सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए श्री कटारूचक ने अधिकारियों को प्रत्येक मंडी में साफ-सफाई, बिजली और स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य को अप्रैल माह के लिए 30,973 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (सीसीएल) प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त राज्य ने 122 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि विभाग ने 132 एलएमटी गेहूं की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इन तैयारियों के तहत 1897 खरीद केंद्रों को अधिसूचित किया गया है और जिला स्तरीय खरीद समितियों (डीएलपीसी) से 266 अतिरिक्त अस्थायी यार्डों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

बारदाने (बोरी) के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने डीएफएससी को मंडियों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा इसकी जिम्मेदारी निरीक्षकों को सौंपने के निर्देश दिए। फसल के भंडारण संबंधी मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पिछले सीजनों की उपज को उठाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष नियमित रूप से यह मुद्दा उठाया गया है, ताकि आगामी सीजनों की उपज के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान उपलब्ध कराया जा सके। श्री कटारूचक ने डीएफएससी को निर्देश दिए कि वे भंडारण व्यवस्था के संबंध में अपने-अपने जिलों के उपायुक्तों (डीसी) के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें और इस संबंध में मुख्यालय को नियमित रूप से अवगत कराते रहें।

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को मंडियों में तिरपाल, लकड़ी के क्रेट आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति के संबंध में भरोसा दिलाया और कहा कि विभाग इन वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ समन्वय बनाए हुए है।

उन्होंने बताया कि आपूर्ति की निगरानी और जनता की शिकायतों के समाधान के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम नंबर 0172-2233001 शुरू किया गया है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों की नियमित और सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्तों के अधीन जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इस अवसर पर अन्य के अलावा प्रमुख सचिव राहुल तिवाड़ी, निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर और अजयवीर सिंह सराओ भी उपस्थित थे।

खाड़ी में कोहराम: ईरान का कुवैत पर बड़ा हमला, भारतीय कर्मचारी की मौत

बिजली-पानी डिसेलिनेशन प्लांट को निशाना बनाकर दागीं मिसाइलें

सर्विस बिल्डिंग को बनाया निशाना, सैन्य शिविरों पर भी बरसे गोले

एजेंसी (हि.स.)
कुवैत सिटी

ईरानी हमले से कुवैत का बिजली और पानी का डिसेलिनेशन (विलवणीकरण संयंत्र) प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया है। कुवैती अधिकारियों का कहना है कि हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई। हमले में इमारत को भौतिक नुकसान पहुंचा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब युद्ध से क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है।

अल जजीरा चैनल और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कुवैत के बिजली मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, ईरान ने देश के एक बिजली और पानी के डिसेलिनेशन प्लांट में स्थित एक सर्विस बिल्डिंग पर हमला किया है। इस हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई और इमारत को काफी भौतिक नुकसान पहुंचा है। बयान के अनुसार, हमले के बाद की स्थिति से निपटने और कामकाज को सामान्य रूप से जारी रखने के लिए तकनीकी और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को तुरंत भेजा गया।

फोटोः हि.स.

ईरान ने अभी तक इस हमले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। सरकारी मीडिया ने कुवैत के मंत्रालय के हवाले से कहा कि हमले के कारण प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कल शाम कहा था कि कुवैत के हवाई क्षेत्र में 14 मिसाइलें और 12 ड्रोन देखे गए। उनमें से कई ड्रोन एक सैन्य शिविर को निशाना बना रहे थे। इस दौरान 10 सैनिक घायल हो गए। पिछले माह 28 फरवरी से अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध समय गुजरने के साथ और आक्रामक हो रहा है। ईरान के आधिकारिक मीडिया के अनुसार, ईरान की संसद के स्पीकर ने अमेरिका को जमीनी हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। धमकी दी है कि अगर ईरान पर जमीनी हमला होता है तो अमेरिकी सहयोगियों पर हमले तेज किए जाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि इजराइल दक्षिणी लेबनान में अपने हमले का दायरा बढ़ाएगा। इजराइली सेना पड़ोसी देश में मौजूदा सुरक्षा पट्टी का विस्तार करेगी।

अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी मूल के इजराइली सैनिक सार्जेंट मोशे यित्जाक हाकोहेन काट्ज दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान मारे गए। डिसेलिनेशन प्लांट का उपयोगः यहां समुद्र के खारे पानी से नमक और अन्य खनिजों को अलग कर उसे पीने योग्य बनाया जाता है। इसका औद्योगिक उपयोग भी किया जाता है। इन संयंत्रों को अकसर पावर प्लांट के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि डिसेलिनेशन एक ऊर्जा-गहन प्रक्रिया है।

बिहार की राजनीति के शिखर पुरुष नीतीश कुमार का सफरनामा

एजेंसी (हि.स.)
पटना

फोटोः हि.स.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार पहली बार 2006 में विधान परिषद के सदस्य बने थे। उसके बाद 2012, 2018 और 2024 में लगातार चौथी बार उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली । विधान परिषद की सदस्यता छह वर्ष के लिए होती है। उनके टर्म इस प्रकार रहे- 2006-2012, 2012-2018, 2018-2024 और 2024 से अब तक। साल 2005 के नवंबर में पहली बार बिहार की सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने हमेशा विधान परिषद के रास्ते मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

उन्होंने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। 1985 में हरनौत से विधायक चुने जाने के बाद वे लोकसभा सदस्य भी रहे और केंद्र में मंत्री पद भी संभाला। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विधानसभा की बजाय विधान परिषद की सदस्यता को प्राथमिकता दी। राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार अब चारों सदनों के सदस्य बन जाएंगे। उन्होंने पहले विधानसभा (विधायक), फिर लोकसभा (सांसद), उसके बाद विधान परिषद और अब राज्यसभा की सदस्यता हासिल कर ली है। यह उनके राजनीतिक करियर में एक अनोखा उपलब्धि मानी जा रही है। विधान परिषद की सदस्यता छोड़ने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना होगा। हालांकि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वे छह महीने तक बिना विधान परिषद या विधानसभा की सदस्यता के मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं. इस दौरान उन्हें या तो विधानसभा चुनाव लड़कर सदस्यता हासिल करनी होगी या फिर कोई अन्य रास्ता अपनाना होगा। साल 1985 से शुरू हुए नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर में राज्यसभा जाना एक नया अध्याय जुड़ गया है। 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता लेने के साथ ही उनके राजनीतिक जीवन का यह नया चरण शुरू होगा।

नीतीश कुमार का विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया । नीतीश कुमार ने यह कदम राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद उठाया। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे विकासशील मुख्यमंत्री हैं। अब केंद्र जा रहे है। उनके नेतृत्व में बिहार ने विकास को देखा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया जा रहा है। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है।

नेपाल में नाबालिग से दुर्व्यवहार के आरोप में यूएमएल की विधायक गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

फोटोः हि.स.

सीपीएन-यूएमएल की लुंबिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा कुमारी शर्मा को नाबालिग घरेलू कामगार के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। काठमांडू की अपराध अन्वेषण कार्यालय की एक टीम ने उन्हें रविवार देर रात काठमांडू के धुम्बाराही स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया। शर्मा यूएमएल की निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हैं। करीब डेढ़ साल पहले उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की को छह वर्षों तक अपने घर में घरेलू कामगार के रूप में रखकर बाल श्रम का शोषण किया और उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया। बताया गया है कि उस लड़की को कई बार पीटा गया, और जब उसकी हालत बिगड़ गई, तब काठमांडू महानगरपालिका ने उसे शर्मा के घर से बचाया। उस समय सरकारी वकील के कार्यालय ने शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज न करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय की व्यापक आलोचना हुई थी, खासकर उस समय जब यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे। बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले की समीक्षा की। राजनीतिक हस्तक्षेप और सत्ता में बैठे लोगों को संरक्षण मिलने के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। तत्कालीन काठमांडू महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह ने भी सार्वजनिक रूप से इस निर्णय पर सवाल उठाया था और पूछा था कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद शर्मा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

नेपाल सरकार ने अपने 100 एक्शन प्लान पर निगरानी के लिए बनाया प्रतिपक्ष.कॉम

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की नई पहल; जनता अब वेबसाइट पर देख सकेगी मंत्रियों के काम का कच्चा चिट्ठा

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

नेपाल सरकार ने सुशासन सुधार से जुड़ी 100 कार्यसूचियों की प्रत्यक्ष निगरानी के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। सरकार द्वारा लाए गए सुशासन सुधार कार्यक्रमों की सीधी निगरानी के उद्देश्य से ह्यप्रतिपक्ष डॉटकमह्ल नामक वेबसाइट शुरू की गई है।

बालेन्द्र शाह के प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद गठित मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में शुक्रवार को स्वीकृत और शनिवार को सार्वजनिक की गई 100 बिंदुओं वाली ह्यसुशासन सुधार कार्यसूचीह्ल की निगरानी के लिए यह वेबसाइट शुरू की गई है। इस वेबसाइट में सरकार की 100 बिंदुओं वाली प्रतिबद्धताओं को मुख्य आधार बनाकर कार्य प्रगति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। वेबसाइट पर यह विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी कि सरकार ने कुल कितनी प्रतिबद्धताएं की थीं, उनमें से कितनी पूरी हो चुकी हैं, कितनों पर काम चल रहा है, कितनी टूट चुकी हैं और कितनों पर अभी तक काम शुरू ही नहीं हुआ है। इसके अलावा, कौन-सा कार्य कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, इसकी जानकारी भी वेबसाइट पर दी गई है। हर बिंदु को पूरा करने के लिए कितने दिन शेष हैं, इसकी सूची भी वेबसाइट में शामिल है। वेबसाइट को सभी के उपयोग के लिए नेपाली और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।

नेपाल में सभी बेटिंग ऐप और वेबसाइट को 24 घंटे के भीतर बंद करने का निर्देश

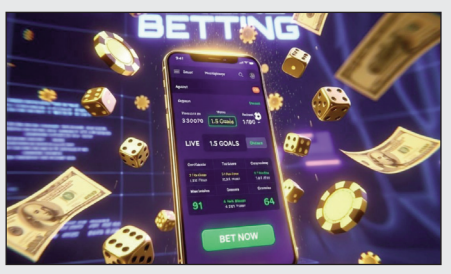

काठमांडू। नेपाल सरकार ने सभी प्रकार के सट्टेबाजी (बेटिंग) ऐप और वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश दिया है। मंत्रिपरिषद की सुशासन सुधार संबंधी 100 कार्यसूची के तहत संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 24 घंटे के भीतर ऐसे प्लेटफॉर्म बंद करने के लिए सभी इंटरनेट सेवा प्रदायक कंपनियों को निर्देश दिया है। संचार मंत्रालय के मंत्रिस्तरीय निर्णय के बाद नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय कर अब तक पहचाने गए सभी सट्टेबाजी साइट और ऐप बंद करा दिए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता उदय बहादुर रानामगर के अनुसार, वर्तमान कानून और अपराध अधिनियम के खिलाफ सट्टेबाजी करना, करवाना या इसे बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन करना गैरकानूनी है। कानूनी प्रावधान के अनुसार सट्टेबाजी में शामिल व्यक्तियों की संपत्ति जब्त की जा सकती है और उन्हें एक वर्ष तक की कैद तथा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मंत्रालय ने सभी से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट का उपयोग न करे। यदि कहीं इस तरह की गतिविधि हो रही हो, तो नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के उपनिदेशक सूर्यप्रसाद लामिछाने से संपर्क कर इसकी जानकारी देने का अनुरोध भी किया गया है।

न्यू मैंगलोर पोर्ट के बर्थ-9 के पुनर्विकास को मंजूरी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

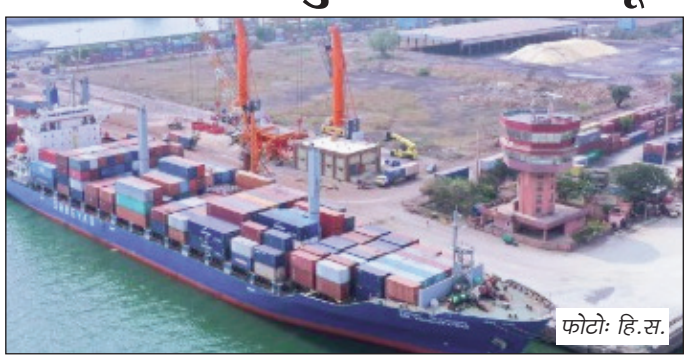
फोटोः हि.स.

केंद्र सरकार ने न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी के बर्थ संख्या-9 के पुनर्विकास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत तरल बल्क कार्गो की हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने और समुद्री दक्षता को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के मुताबिक,यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत डीबीएफओटी आधार पर लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत पुराने ढांचे को हटाकर बर्थ संख्या-9 का आधुनिक तरीके से पुनर्विकास किया जाएगा, जहां कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और एलपीजी जैसे तरल कार्गो की हैंडलिंग की जाएगी।

परियोजना के तहत बर्थ की गहराई वर्तमान 10.5 मीटर से बढ़ाकर 14 मीटर की जाएगी, जिसे भविष्य में 19.8 मीटर तक बढ़ाने की व्यवस्था भी होगी। इससे 2 लाख डीडब्ल्यूटी तक के बड़े जहाजों, जिनमें वीएलजीसी भी शामिल हैं, को संभालना संभव होगा।

केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सबार्नंद सोनोवाल ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के समुद्री बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़कर 10.90 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी और भारत वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा।

उन्होंने कहा कि करीब 438.29 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए निजी भागीदार द्वारा विकसित किया जाएगा। परियोजना की निर्माण अवधि 2 वर्ष और कुल कंसेशन अवधि 30 वर्ष निर्धारित की गई है। परियोजना के तहत आधुनिक मशीनरी और तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें उच्च क्षमता वाले मरीन अनलोडिंग आर्म्स और स्वचालित मूरिंग सिस्टम शामिल हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए आधुनिक अग्निशमन प्रणाली और अन्य उन्नत नियंत्रण तंत्र भी स्थापित किए जाएंगे।

फ्लैट लिस्टिंग के बाद उछले स्पेशलिटी मेडिसिन्स के शेयर

नई दिल्ली। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी स्पेशियलिटी मेडिसिन्स लिमिटेड के शेयरों ने सोमवार स्टॉक मार्केट में फ्लैट एंट्री की। हालांकि लिस्टिंग के बाद खरीदारी शुरू होने से आईपीओ निवेशक मामूली फायदे में आ गए। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 124 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। सोमवार बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग बिना किसी बदलाव के 124 रुपये के स्तर पर ही हुई। लिस्टिंग के बाद खरीदारों ने लिवाली का जोर बनाया, जिससे ये शेयर उछल कर 129.50 रुपये के स्तर तक पहुंचा। हालांकि इसके बाद बिकवाली शुरू हो गई, जिसके कारण इस शेयर की चाल में गिरावट आ गई। दोपहर 11:15 बजे तक के कारोबार के बाद कंपनी के शेयर 124.50 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इस तरह अभी तक के कारोबार के बाद कंपनी के आईपीओ निवेशक पचास पैसे प्रति शेयर यानी 0.40 प्रतिशत के फायदे में थे। स्पेशियलिटी मेडिसिन्स लिमिटेड का 29.14 करोड़ रुपये का आईपीओ 20 से 24 मार्च के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 2.27 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

मणिपुर में केसीपी (पीडब्ल्यूजी) कैडर गिरफ्तार, हथियार और आईईडी बरामद

एजेंसी (हि.स.)
इंफाल

मणिपुर में पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन केसीपी (पीड्ब्ल्यूजी) के एक कैडर को गिरफ्तार किया है। साथ ही भारत-म्यांमार सीमावर्ती इलाकों से एक अन्य अभियान में हथियार एवं आईईडी बरामद किया गया है। मणिपुर पुलिस मुख्यालय के अनुसार, रविवार (28 मार्च) को इंफाल पश्चिम जिले में कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (पीपल्स वॉर ग्रुप) [केसीपी - पीडब्ल्यूजी] से जुड़े एक कथित वसूली गतिविधियों में शामिल कैडर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मैबम पिंकू सिंह (42) के रूप में हुई है, जो चिंगमाथक पिशुम लेइराक का निवासी है। उसे इंफाल पश्चिम जिले में सिंगजामेई पुलिस थानांतर्गत संगाइप्रौ मामंग लेइकाई इलाके से पकड़ा गया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक मोबाइल फोन और एक मतदाता फोटो पहचान पत्र जब्त किया गया। वहीं शनिवार (29 मार्च) को चलाए गए एक अलग अभियान में, सुरक्षा बलों ने तेंगनौपाल जिले में मोरेह पुलिस थानांतर्गत एक दिन पहले एक अलग अभियान में, तेंगनौपाल जिले में भारत-म्यांमार सीमा के बॉर्डर पिलर-73 के पास यांगौबुंग गांव से हथियारों और विस्फोटकों का एक जखीरा बरामद किया। बरामद की गई वस्तुओं में छह 9 एमएम की पिस्तौल, छह 9 एमएम की मैगजीन, एक सिंगल-बैरल राइफल, 15 आईईडी और दो टैक्टिकल रेडियो सेट शामिल हैं। बताया गया है कि मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आईईडी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां जांच जारी रखे हुए हैं।

संक्षिप्त-समाचार

दिल्ली मेट्रो पोस्टर मामले में आतंकी संगठन का कथित संचालक गिरफ्तार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चर्चित मेट्रो पोस्टर मामले में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े मॉड्यूल के कथित संचालक शबीर अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शबीर अहमद लोन हाल ही में सामने आए मेट्रो पोस्टर प्रकरण में सक्रिय आतंकी गिरोह का संचालन कर रहा था। जांच में पता चला है कि वह गिरोह के सदस्यों को निर्देश देने और उनकी गतिविधियों का समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि आरोपित की गिरफ्तारी से इस नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग मिलने की संभावना है। फिलहाल उससे गहन पूछताछ की जा रही है।

आरबीआई के नीतिगत हस्तक्षेप के बाद सुधरा रुपया

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपये की लगातार कीमतों को थामने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप करने के बाद इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सोमवार भारतीय मुद्रा रुपये ने सोमवार शानदार रिकवरी करते हुए 1.22 रुपये की मजबूती के साथ 93.59 रुपये प्रति डॉलर के स्तर से कारोबार की शुरूआत की। इसके पहले पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले अभी तक के सबसे निचले स्तर 94.85 रुपये प्रति डॉलर तक गिरने के बाद 94.81 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। सोमवार शुरूआती कारोबार में ही भारतीय मुद्रा सुधर कर 93.55 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच गई। इस तरह बाजार खुलने के कुछ देर बाद ही रुपये ने अभी तक के सबसे निचले स्तर से 1.30 रुपये की रिकवरी करने में सफलता हासिल की। हालांकि जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा वैसे-वैसे रुपये की कमजोरी एक बार फिर बढ़ने लगी। सुबह 10:30 बजे तक का कारोबार होने के बाद रुपया ओपनिंग लेवल से 71 पैसे टूट कर 94.30 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर कारोबार कर रहा था। मुद्रा बाजार के अभी तक कारोबार में रुपये ने डॉलर के साथ ही ब्रिटिश पौंड (जीबीपी) और यूरो के मुकाबले भी मजबूत प्रदर्शन किया है। सुबह 10:30 बजे तक के कारोबार के बाद ब्रिटिश पौंड (जीबीपी) की तुलना में रुपया 1.05 रुपये की मजबूती के साथ 125.07 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह सुबह 10:30 बजे तक कारोबार होने के बाद यूरो की तुलना में रुपया 63.97 पैसे की बढ़त के साथ 108.56 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

सराफा बाजार में मामूली गिरावट, सोना और चांदी की फीकी पड़ी चमक

नई दिल्ली। घरेलू सराफा बाजार में सोमवार शुरूआती कारोबार के दौरान सांकेतिक गिरावट का रुख नजर आ रहा है। कीमत में आई इस गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना सोमवार 1,48,060 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,48,210 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना आज 1,35,740 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,35,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी मामूली कमजोरी आने के कारण ये चमकीली धातु आज शुरूआती कारोबार कै दौरान दिल्ली सराफा बाजार में 2,44,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर बिक रही है। दिल्ली में सोमवार 24 कैरेट सोना 1,48,210 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,890 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,48,060 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,35,740 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,48,110 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,790 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,48,060 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,35,740 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,48,060 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,35,740 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत एशिया में भी बिकवाली का दबाव

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

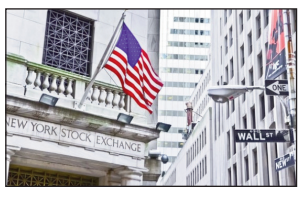

पश्चिम एशिया में जारी जंग के और तेज होने की आशंका और हूती विद्रोहियों के भी इस जंग में शामिल हो जाने के कारण सोमवार ग्लोबल मार्केट पर दबाव बना हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के ज्यादातर शेयर बाजार बड़ी गिरावट का संकेत दे रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान गिरावट का शिकार होकर बंद हुए। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स भी आज मामूली कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार बिकवाली होती रही। इसी तरह एशियाई बाजार में भी आज आमतौर पर कमजोरी का रुख बना हुआ है। अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा, जिसकी वजह से वॉल स्ट्रीट के सूचकांक कमजोरी के साथ बंद हुए। एस एंड पी 500 इंडेक्स 108.31 अंक यानी 1.67 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 6,368.85 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 459.72 अंक यानी 2.15 प्रतिशत फिसल कर 20,948.36 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज फिलहाल 0.03 प्रतिशत की मामूली कमजोरी के साथ 45,154.57 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान कमजोरी बनी रही। एफटीएसई इंडेक्स 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 9,967.35 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.87 प्रतिशत लुढ़क कर 7,701.95 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 312.22 अंक यानी 1.40 प्रतिशत टूट कर 22,300.75 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

इतिहास रचने की तैयारी **आर्टेमिस II मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह तैयार, प्रक्षेपण एक अप्रैल को**

53 साल बाद फिर चांद की दहलीज पर कदम रखेगा इंसान

एजेंसी (हि.स.)
वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) के पहले मानवयुक्त मिशन 'आर्टेमिस क्क्क' के चारों अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह तैयार हैं। इस मिशन का प्रक्षेपण एक अप्रैल को होना है। चारों अंतरिक्ष यात्री कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन विशेषज्ञ क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसन ने कहा कि हमें इस पल का इंतजार हैं। हम इस ऐतिहासिक प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) के अनुसार, आधिकारिक तौर पर 49 घंटे और 40 मिनट की उलटी गिनती सोमवार (31 मार्च) को भारतीय समयानुसार देर रात (4:44 बजे पूर्वी समयानुसार) शुरू होने वाली है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो रॉकेट 1 अप्रैल को शाम 6:24 बजे (पूर्वी डेलाइट समय) फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। कमांडर वाइसमैन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी टीम और रॉकेट दोनों पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी भी स्थिति (जैसे कि तकनीकी कारणों से प्रक्षेपण टलना) के लिए मानसिक रूप से 100 प्रतिशत तैयार हैं। आर्टेमिस क्क्कमिशन का उद्देश्य 50 से अधिक वर्ष के बाद मनुष्य को फिर से चंद्रमा के करीब ले जाना है। यह मिशन 1972 के अपोलो 17 के बाद चंद्रमा की ओर जाने वाला पहला मानव मिशन है।

यह चंद्रमा के चारों ओर एक फ्लाईबाई (परिक्रमा) करेगा। यह चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेगा, बल्कि भविष्य के आर्टेमिस क्क्कक के लिए प्रणालियों का परीक्षण करेगा। यह लगभग 10 दिन की यात्रा होगी। चालक दल ओरियन कैप्सूल (अंतरिक्ष यान) में यात्रा करेगा। यह मिशन नासा को अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ओरियन के जीवन-सहायक प्रणालियों के परीक्षण करने की अनुमति देगा। चारों अंतरिक्ष यात्री कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर

फोटोः हि.स.

ग्लोवर, मिशन विशेषज्ञ क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसन शुक्रवार को ह्यूस्टन से केनेडी स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं। मेडिकल क्वारंटाइन में रहते हुए उन्होंने रविवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। वाइसमैन 2019-20 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 328 दिनों के अभियान के दौरान छह बार स्पेस वॉक कर चुके हैं। वाइसमैन ने कहा, यह पहली बार है जब हम इंसानों को अपने साथ ले जा रहे हैं। यह सब सपने जैसा लगता है। मुझे आराम महसूस हो रहा है। यहां होना अच्छा लग रहा है। उधर, मौसम विज्ञानियों का कहना है कि मौसम के ठीक रहने की 80 प्रतिशत संभावना है। ग्राउंड सिस्टम मैनेजर शॉन क्विन ने कहा, आर्टेमिस क्क्कमिशन 53 साल में चांद पर वापस जाने वाली पहली इंसानी उड़ान है। इस मिशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लॉन्च होने के 25 घंटे बाद चांद की ओर रवाना होने से पहले, ओरियन क्रू कैप्सूल के प्रोपल्शन, नेविगेशन, कम्युनिकेशन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की अच्छी तरह से जांच की जा सके। चारों अंतरिक्ष यात्री न तो चांद पर उतरेंगे और न ही चांद की कक्षा में जाएंगे। इसके बजाय, वे चांद के दूसरी तरफ से घूमकर आएंगे। वे चांद की ग्रैविटी का इस्तेमाल करके कैप्सूल के रास्ते को वापस पृथ्वी की ओर मोड़ेंगे।

10 अप्रैल को रात लगभग आठ बजे (पूर्वी समयानुसार) सैन डिएगो के पास दक्षिणी कैलिफोर्निया के तट से दूर प्रशांत महासागर में कैप्सूल की लैंडिंग होगी। उन्होंने कहा कि अगर चारों बुधवार को दो घंटे की लॉन्च विंडो के शुरू होते ही उड़ान भरते हैं, तो वे पृथ्वी से इतनी दूर तक जाएंगे जितनी दूर तक उनसे पहले कोई भी इंसान नहीं गया है। वे 252,799 मील की दूरी तय करेंगे। यह 1970 में अपोलो 13 के क्रू के बनाए गए रिकॉर्ड से लगभग 4,144 मील ज्यादा है। इस मिशन को एक तरह से नई राह दिखाने वाला माना जा रहा है। यह अगले साल पृथ्वी की कक्षा में होने वाली एक उड़ान के लिए जमीन तैयार करेगा। नासा की योजना है कि इस उड़ान के बाद, 2028 में चांद पर एक या दो लैंडिंग की जाएं।

फिडे कैंडिडेट्स 2026: पहले दौर में आर. प्रज्ञानानंद की शानदार जीत

महिला वर्ग में दिव्या और वैशाली की सधी हुई शुरूआत

कारुआना ने नाकामुरा को मैराथन मुकाबले में हराया

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फिडे कैंडिडेट्स 2026 के पहले दौर में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को उच्च वरीयता प्राप्त अनीश गिरी को पराजित कर अपने अभियान की शानदार शुरूआत की। प्रज्ञानानंद ने मुकाबले को अंतिम चरण तक खींचते हुए गिरी पर लगातार दबाव बनाए रखा। लगभग 40 चालों के बाद भारतीय खिलाड़ी ने एक प्यादा बढ़त के साथ निर्णायक बढ़त बना ली, जिससे गिरी की वापसी की संभावना समाप्त हो गई। दिन के सबसे चर्चित मुकाबले में अमेरिका के फैबियानो कारुआना ने हमवतन हिकारू नाकामुरा को रोमांचक और लंबे मुकाबले में मात दी। यह पहला दौर का सबसे लंबा खेल रहा। अन्य मुकाबलों में उज्बेकिस्तान के जवोखिर सिंदारोव ने रूस के आंद्रेई एसिपेंको को हराया, जबकि जर्मनी के मैथियास ब्लूबाम और चीन के वेई यी के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। महिला वर्ग में भारत की युवा ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख ने शुरूआती चरण में आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन यूक्रेन की अन्ना मुज़िचुक ने संयम बनाए रखते हुए मुकाबले को बराबरी पर समाप्त किया। उन्होंने समय रहते मोहरों की अदला-बदली कर स्थिति को संतुलित कर दिया। एक अन्य मुकाबले में आर. वैशाली ने कजाखस्तान की बिबीसारा असाउबायेवा के खिलाफ सतर्क रणनीति अपनाते हुए मुकाबला बराबरी पर छोड़ा। मध्य चरण में वैशाली दबाव में दिखीं और समय भी कम था, लेकिन उन्होंने अंतिम क्षणों में सटीक चाल चलकर खेल को अतिरिक्त समय तक पहुंचाया और अंततः परिणाम बराबरी रहा। चीन की ज़ू जिनर और तान झोंगयी के बीच मुकाबला उतार-चढ़ाव भरा रहा और अंत में बराबरी पर समाप्त हुआ।

फोटोः हि.स.

परिणाम (पहला दौर)

ओपन वर्गः जवोखिर सिंदारोव ने आंद्रेई एसिपेंको को हराया; मैथियास ब्लूबाम और वेई यी के बीच मुकाबला बराबरी पर रहा; आर. प्रज्ञानानंद ने अनीश गिरी को पराजित किया; फैबियानो कारुआना ने हिकारू नाकामुरा को हराया।

महिला वर्गः दिव्या देशमुख और अन्ना मुज़िचुक के बीच मुकाबला बराबरी पर रहा; आर. वैशाली और बिबीसारा असाउबायेवा के बीच खेल अनिर्णीत रहा; अलेक्जेंड्रा गोरियाच्किना और कैटरीना लाग्नो का मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ; झू जिनर और तान झोंगयी के बीच भी खेल बराबरी पर रहा।

मियामी ओपन 2026: यानिक सिनर ने जीरी लेहेका को हराकर जीता खिताब

रचा 'सनशाइन डबल' का इतिहास

एजेंसी (हि.स.)
मियामी

फोटोः हि.स.

मियामी ओपन के बारिश से प्रभावित फाइनल में इटली के स्टार खिलाड़ी यानिक सिनर ने रविवार रात चेक गणराज्य के जीरी लेहेका को 6-4, 6-4 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ सिनर बिना एक भी सेट गंवाए 'सनशाइन डबल' पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। विश्व नंबर दो सिनर ने मुकाबले में अपने पहले सर्विस पर 92 प्रतिशत अंक जीते और पूरे मैच के दौरान मिले तीनों ब्रेक प्वाइंट बचाए।

इस जीत के साथ उन्होंने मास्टर्स 1000 मुकाबलों में बिना सेट गंवाए अपनी जीत की श्रृंखला को 17 तक पहुंचा दिया। मुकाबले के बाद सिनर ने कहा, हमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। अब घर लौटने को लेकर भी उत्साहित हूं। पहली बार सनशाइन डबल हासिल करना मेरे लिए अविश्वसनीय है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव हो पाएगा। बारिश के कारण मुकाबला लगभग 90 मिनट देर से शुरू हुआ। इसके बावजूद सिनर ने शानदार शुरूआत करते हुए पहले सेट में जल्दी 3-1 की बढ़त बनाई और मजबूत सर्विस के दम पर सेट अपने नाम किया।

दूसरे सेट की शुरूआत में फिर बारिश के चलते खेल रोकना पड़ा, लेकिन वापसी के बाद सिनर ने अपना दबदबा कायम रखा। लेहेका, जो अपने करियर का पहला मास्टर्स 1000 फाइनल खेल रहे थे, ने दूसरे सेट में कड़ा मुकाबला दिया। उन्होंने कई ब्रेक प्वाइंट बचाए और एक समय 4-3 की बढ़त भी बना ली, लेकिन सिनर ने निर्णायक क्षणों में बेहतर खेल दिखाते हुए वापसी की। सिनर ने दूसरे सेट में अपने छठे ब्रेक प्वाइंट पर सफलता हासिल कर 5-4 की बढ़त बनाई और फिर अपनी सर्विस पर मैच जीत लिया।

गौरतलब है कि सिनर 2017 में रोजर फेडरर के बाद पहले खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने इंडियन वेल्स और मियामी ओपन खिताब लगातार जीते हैं। इस उपलब्धि को 'सनशाइन डबल' कहा जाता है। इस खास उपलब्धि के साथ सिनर ने नोवाक जोकोविच, आंद्रे आगासी, पीट सैम्प्रास, माइकल चांग और जिम कूरियर जैसे महान खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने कहा कि केकेआर को पता है कि ग्रीन गेंदबाजी नहीं कर सकेंगे

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
सिडनी

क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने सोमवार को कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स प्रबंधन को कैमरन ग्रीन की चोट की स्थिति के बारे में पूरी तरह से पता है जबकि केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल के पहले मैच में मिली हार के बाद कहा था कि सिर्फ मेजबान बोर्ड को ही पता है कि ग्रीन गेंदबाजी क्यो नहीं कर सके। ग्रीन से गेंदबाजी नहीं कराने के बारे में पूछे गए सवालों पर रहाणे ने कहा , क्रिकेट आस्ट्रेलिया से पूछो । क्रिकेट आस्ट्रेलिया के एक प्रवक्ता ने बताया , कैमरन को कमर में चोट लगी थी जिससे वह कुछ समय तक गेंदबाजी नहीं कर सकेगा । वह 10.12 दिन के बाद गेंदबाजी कर पायेगा और केकेआर को इसकी पूरी जानकारी है ।

ग्रीन ने सितंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक गेंदबाजी नहीं की । उन्होंने 20 फरवरी को ओमान के खिलाफ टी20 विश्व कप के मैच में गेंदबाजी की थी । पूरे विश्व कप में वह 19 गेंद ही डाल सके । केकेआर ने 25 . 20 करोड़ रुपए में ग्रीन को खरीदा था जो सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने ।

शाहीन अफरीदी, सिकंदर रजा ने होटल का सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ा

लाहौर। पाकिस्तान सुपर लीग की लाहौर कलंदर्स टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी और विदेशी खिलाड़ी सिकंदर रजा को उनके होटल का टीम सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का दोषी पाया गया है । मोहम्मद फैसल (लाहौर डीआईजी ,आपरेशंस) ने पीएसएल के सीईओ को बताया कि शहर के पांच सितारा होटल में जहां आठ टीमें ठहरी हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन हुआ है । पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूर्व चेतावनी और मनाही के बावजूद शाहीन और सिकंदर ने रजा के आठवें माले स्थित कमरे में रात डेढ बजे तक चार मेहमानों की मेजबानी की । लाहौर कलंदर्स के मीडिया अधिकारी ने रजा के कमरे में 10 . 35 तक और फिर रात 11 बजे तक मेहमानों के रहने की अनुमति मांगी थी लेकिन दोनों खारिज कर दी गई थी । इसके बाद टीम के मालिक ने पीएसएल सीईओ सलमान नसीर से यही अनुरोध किया था जो सुरक्षा कारणों से खारिज कर दिया गया था ।

पीएसएल में बॉल टेम्परिंग विवादः फखर जमान ने आरोपों से किया इनकार, 48 घंटे में आएगा फैसला

एजेंसी (हि.स.)
लाहौर

पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान कथित बॉल टेम्परिंग मामले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। लाहौर के स्टार बल्लेबाज फखर जमान पर कराची की पारी के अंतिम ओवर से पहले गेंद की स्थिति बदलने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में फखर जमान अपने साथियों हैरिस रऊफ और कप्तान शाहिद अफरीदी के साथ चर्चा करते नजर आए।

इसी दौरान ऑन-फील्ड अंपायर फैसल अफरीदी को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने हस्तक्षेप किया। अंपायर ने गेंद की जांच के बाद पाया कि उसकी स्थिति से छेड़छाड़ की गई है। इसके चलते कराची किंग्स को पांच रन का पेनल्टी दिया गया और अंतिम ओवर के लिए नई गेंद उपलब्ध कराई गई। इस फैसले ने मैच का रुख बदल दिया। मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बयान जारी कर बताया कि फखर जमान पर लेवल-3 का आरोप लगाया गया है। यह आरोप खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के आचार संहिता के अनुच्छेद 2.14 के तहत है, जिसमें गेंद की स्थिति बदलना अपराध माना जाता है।

फोटोः हि.स.

मैच रेफरी रोशन महानामा की अगुवाई में हुई सुनवाई में फखर जमान ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। बोर्ड के अनुसार, अगले 48 घंटे में एक और सुनवाई होगी, जिसके बाद अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। मैच में अंपायरों द्वारा पांच रन की पेनल्टी दिए जाने के बाद कराची किंग्स को आखिरी ओवर में 9 रन की जरूरत थी, जिसे टीम ने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। ऑलराउंडर अब्बास अफरीदी ने रऊफ की गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। अगर मैच रेफरी आरोपों की पुष्टि करते हैं, तो फखर जमान और लाहौर कलंदर्स टीम को कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें निलंबन या भारी जुमार्ना शामिल हो सकता है।

सूर्या को इंपैक्ट सब के तौर पर एहतियातन इस्तेमाल किया गया : जयवर्धने

एजेंसी (हि.स.)
मुंबई

फोटोः हि.स.

मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने कहा कि भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को टीम के पहले आईपीएल मैच में चोट के कारण 'इंपैक्ट सब' के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसमें कोई गैर जरूरी कहानी बनाने की जरूरत नहीं है । कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में सूर्यकुमार ने फील्डिंग नहीं की और आठ गेंद में 16 रन बनाये । मुंबई ने केकेआर को छह विकेट से हराया । मैच के बाद जयवर्धने से पूछा गया कि पिछले सत्र में भारत और मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के बाद क्या अब सूर्यकुमार यादव को 'इंपैक्ट सब' के तौर पर इस्तेमाल किया जायेगा, इस पर उन्होंने कहा , उम्मीद है कि कोई अवांछित कहानी नहीं बनाई जायेगी । टीम खुश है । उसे अतिरिक्त ब्रेक दिया गया था जो वह चाहता था । उन्होंने कहा ,उसे मामूली सी जकड़न है और वह फील्डिंग वगैरह कर रहा था । मुझे पता है कि अगले मैच में पांच दिन का समय है तो उसे अतिरिक्त समय देना चाहता था । वह तीन चार ओवर फील्डिंग के लिये तत्पर था लेकिन मैने मना किया । जयवर्धने ने कहा ,इसलिये प्लीज कोई कहानियां मत बनाइये । मैने कहा कि एहतियात के तौर पर ऐसा किया गया था । ये काफी अनमोल खिलाड़ी हैं और ये फैसले सोच समझकर लिये जाते हैं । उन्होंने खुशी जताई कि आखिरकार मुंबई इंडियंस ने पहला मैच हारने का सिलसिला तोड़ा । रोहित (78) और रियान रिकेलटन (81) की पारियों के दम पर मुंबई ने 221 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल किया ।

समाज की मुख्यधारा में अपनी जगह तलाशता ट्रांसजेंडर समुदाय

दुनिया भर में हर साल 31 मार्च को मनाया जाने वाला 'इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी' केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सुधार की कहानी है। दशकों तक ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ी खबरें केवल 'हिंसा', 'भेदभाव' या 'शोक' तक सीमित रहीं। समाज उन्हें केवल पीड़ित के रूप में देखता था। इसी धारणा को बदलने के लिए साल 2009 में मिशिगन की प्रसिद्ध कार्यकर्ता राचेल क्रैंडल ने इस दिन की नींव रखी। इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य कारण 'दुख' के बजाय 'गौरव' को सामने लाना था। इसका उद्देश्य दुनिया को यह दिखाना है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति केवल हाशिए पर रहने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वे हमारे समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील और कलाकार हैं। यह दिन समाज को यह याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि इस समुदाय को दया की नहीं, बल्कि 'विजिबिलिटी' यानी अपनी पहचान के साथ सम्मानपूर्वक जीने और मुख्यधारा में शामिल होने के समान अवसरों की आवश्यकता है। आज के दौर में, जब भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय अपनी कानूनी पहचान और 2026 के नए संशोधनों के बीच संघर्ष कर रहा है, यह दिन और भी प्रासंगिक हो जाता है। यह दिन सवाल पूछता है कि क्या हम एक ऐसा समाज बन पाए हैं जहाँ किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसके जेंडर के बजाय उसकी काबिलियत से पहचाना जाए? आइए, समझते हैं इस दिन के गहरे उद्देश्यों और इसके संघर्षपूर्ण सफर को।

इतिहास

इस दिन की कहानी साल 2009 में शुरू हुई थी। इससे पहले, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए साल का सबसे प्रमुख दिन 'ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेंब्रेंस' (20 नवंबर) हुआ करता था। वह दिन उन लोगों की याद में मनाया जाता था जिन्होंने नफरत और हिंसा के कारण अपनी जान गंवा दी थी। मिशिगन की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता राचेल क्रैंडल ने महसूस किया कि हालांकि अपनों को खोने का दुख मनाना जरूरी है, लेकिन समुदाय को एक ऐसे दिन की भी जरूरत है जो उनकी 'जीवित मौजूदगी' और 'सफलता' का जश्न मनाए। राचेल का मानना था कि दुनिया को केवल यह नहीं देखना चाहिए कि हमें कैसे मारा जा रहा है, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि हम कैसे जी रहे हैं, कैसे डॉक्टर, इंजीनियर और कलाकार बनकर समाज में योगदान दे रहे हैं। इसी विचार के साथ 31 मार्च 2009 को पहली बार यह दिन मनाया गया।

महत्व

आज के दौर में इस दिन का महत्व केवल प्रतीकात्मक नहीं रह गया है। यह दिन एक 'मिरर' (आईना) की तरह काम करता है, जो सरकारों और व्यवस्थाओं को उनकी कमियां दिखाता है। भारत जैसे देश में, जहाँ 2014 के 'नालसा' फैसले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तीसरे लिंग' के रूप में पहचान दी, वहां यह दिन संविधान द्वारा दिए गए 'समानता के अधिकार' की याद दिलाता है। जब एक ट्रांसजेंडर युवा मीडिया या समाज में अपने जैसे सफल लोगों को देखता है, तो उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। यह दिन आत्म-स्वीकृति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर कई तरह की रूढ़िवादी धारणाएं हैं। यह दिन उन भ्रांतियों को तोड़कर उनके वास्तविक मानवीय पक्ष को सामने लाता है।

उद्देश्य

इस अंतरराष्ट्रीय दिवस के मुख्य रूप से तीन बड़े उद्देश्य हैं: जागरूकता और शिक्षा: आम जनता को जेंडर आइडेंटिटी (लैंगिक पहचान) और सेक्सुअल ओरिएंटेशन (यौन अभिविन्यास) के बीच के महीन अंतर को समझाना। ताकि लोग 'ट्रांसजेंडर' होने को कोई बीमारी या अभिशाप न समझें। कार्यस्थलों, स्कूलों और अस्पतालों में होने वाले सूक्ष्म भेदभाव को खत्म करना। इसका उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपनी पहचान छिपाकर नौकरी न करनी पड़े। सरकारों पर दबाव बनाना कि वे ऐसे कानून लाएं जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति, गोद लेने के अधिकार और विवाह जैसे नागरिक अधिकार प्रदान करें। 2026 के संशोधनों के बीच, यह उद्देश्य और भी गंभीर हो गया है क्योंकि अब लड़ाई अपनी पहचान को मेडिकल सर्टिफिकेट से मुक्त रखने की है।

एक शुरूआत जो बदलाव की मशाल बनी

इस दिन की शुरूआत साल 2009 में हुई थी। अमेरिका की जानी-मानी ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता राचेल क्रैंडल ने महसूस किया कि ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ी ज्यादातर खबरें केवल 'हिंसा' या 'शोक' (ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेंब्रेंस) के इर्द-गिर्द सिमटी रहती हैं। उन्होंने चाहा कि एक ऐसा दिन हो, जो उनके दुख पर नहीं, बल्कि उनके गौरव और सफलता पर केंद्रित हो। तब से यह दिन दुनिया भर में फैल गया और आज यह एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है।

भारतः अदालती जीत और जमीनी हकीकत का फासला

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का सफर कानूनी रूप से 2014 के 'नालसा' फैसले से तेजी से बदला था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए उन्हें 'थर्ड जेंडर' के रूप में मान्यता दी और स्पष्ट किया कि अपनी लैंगिक पहचान तय करने का अधिकार व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है। इसके बाद 2019 का कानून आया, जिसने भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की नींव रखी। लेकिन 2026 का नया संशोधन विधेयक इस पूरे ढांचे को हिलाता हुआ नजर आ रहा है। नए कानून में 'स्व-पहचान' के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। अब पहचान पत्र के लिए एक मेडिकल बोर्ड की सिफारिश अनिवार्य की जा रही है। 29 वर्षीय रिसर्च स्कॉलर प्रत्यय कहती हैं, 2019 के कानून ने हमें सिर उठाकर जीने की उम्मीद दी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मेरी पहचान सरकार के हाथों में है, मेरे अपने अहसास में नहीं। क्या मेरा अस्तित्व साबित करने के लिए मुझे अब किसी डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी ?

विजिबिलिटीः सिर्फ दिखने और देखे जाने के बीच का अंतर

अक्सर 'विजिबिलिटी' का मतलब केवल शारीरिक उपस्थिति से लिया जाता है, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। इसका अर्थ है- स्कूल के रजिस्टर में अपना चुना हुआ नाम देखना, दफ्तर के आईडी कार्ड पर अपनी सही पहचान पाना और अस्पतालों में बिना किसी हिचक के इलाज कराना। आंकड़े बताते हैं कि भारत में आज भी करीब 31 प्रतिशत ट्रांसजेंडर युवा आत्महत्या जैसा कदम उठाने के बारे में सोचते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वह 'अदृश्यता' है जो समाज उन पर थोपता है। जब एक बच्चा अपनी पहचान को लेकर उलझन में होता है, तो उसे घर में 'बीमार' समझा जाता है और बाहर 'मजाक' बनाया जाता है। 37 वर्षीय मोना की कहानी इसका जीता-जागता उदाहरण है। 15 साल की उम्र में मेकअप और लड़कियों जैसे कपड़े पहनने की चाहत ने उन्हें घर से बेदखल करवा दिया। वे कहती हैं, विजिबिलिटी का मतलब हमारे लिए तब होगा, जब हमें भी बाकी लोगों की तरह किराया पर घर मिल सके और नौकरी के इंटरव्यू में हमारी काबिलियत देखी जाए, हमारा जेंडर नहीं।

पंजाब लोक भवन में राजस्थान और ओडिशा के स्थापना दिवस समारोह पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

राजस्थान और ओडिशा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पंजाब लोक भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता कटारिया के साथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने दोनों राज्यों के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि राजस्थान अपनी वीरता और साहस के लिए जाना जाता है, जबकि ओडिशा भक्ति और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर भारत की साझा पहचान को प्रतिबिंबित करते हैं। उन्होंने ह्यएक भारत श्रेष्ठ भारतह्ल की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पहल राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान, बेहतर समझ और एकता को बढ़ावा देती है।

राजस्थान की प्रस्तुति में सुश्री गीतांजलि खंडेलवाल, आईपीएस का संबोधन शामिल था, जिसके बाद पारंपरिक वाद्ययंत्रों पर आधारित ह्लडेजर्ट सिम्फनीह्ल प्रस्तुत की गई। आंगी गैर, भवाल, कथक, सहारिया स्वांग, घूमर और कालबेलिया जैसे लोक एवं शास्त्रीय नृत्यों ने राज्य की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया। ओडिशा की प्रस्तुति में डॉ. आर. के. राठू का संबोधन, सांबलपुरी लोक नृत्य की उत्साहपूर्ण प्रस्तुति तथा श्री शनि धनुक द्वारा राज्यपाल का लाइव पोर्ट्रेट चित्रण शामिल था, जिसने कार्यक्रम में कलात्मक आयाम जोड़ा। इन प्रस्तुतियों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और राष्ट्रीय एकता की भावना को उजागर किया।

राज्यपाल ने मानवता का संदेश देते हुए लोगों से अहंकार और क्रोध से ऊपर उठने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मानवता की भावना भारत की मिट्टी में गहराई से रची-बसी है। भगवान महावीर की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए, विशेष रूप से महावीर जयंती के संदर्भ में, उन्होंने क्षमा, अहिंसा और सद्भाव के मूल्यों पर प्रकाश डाला। राजस्थान के बारे में बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह राज्य अपने समृद्ध इतिहास, किलों, लोक परंपराओं, हस्तशिल्प, व्यंजनों और आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कालीबंगन जैसे पुरातात्विक स्थलों, चित्तौड़गढ़ और आमेर जैसे ऐतिहासिक किलों तथा घूमर और कालबेलिया जैसे प्रसिद्ध नृत्यों का उल्लेख करते हुए राजस्थान की सांस्कृतिक समृद्धि को रेखांकित किया।

ओडिशा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह राज्य गौरवशाली सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का धनी है। उन्होंने कलिंग की विरासत, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिसी नृत्य, जनजातीय परंपराएँ, साहित्य, जैव विविधता तथा स्वतंत्रता संग्राम और आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका का उल्लेख किया। राज्यपाल ने कहा कि स्थापना दिवसों का संयुक्त रूप से आयोजन राज्यों के बीच परस्पर सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में निहित है और ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में सहायक होते हैं। उन्होंने नागरिकों से दोनों राज्यों की समृद्ध विरासत से प्रेरणा लेकर एक मजबूत और प्रगतिशील भारत के निर्माण हेतु मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां; विधायक डॉ. नच्छत्तर पाल; भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन; पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक प्रताप सिंह; गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़; पुलिस महानिदेशक, चंडीगढ़, डॉ. सागरप्रीत हुड्डा; उपायुक्त, चंडीगढ़, निशांत कुमार यादव; शिवदुलार सिंह, सचिव, रेड क्रॉस, पंजाब; सेवानिवृत्त आईएएस प्रियदर्शिनी ठाकुर; पूर्व मेयर हरप्रीत कौर बबला तथा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

गृहस्थ में रहते हुए अध्यात्म जरूरी: सुदीक्षा जी महाराज

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

संत निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन पवित्र आशीर्वाद से आज सेक्टर 15 चंडीगढ़ स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में ₹महिला समागम₹ का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं ने विचारों, गीतों, कविताओं व स्किट आदि के माध्यम से सतगुरु की शिक्षाओं का यशोगान किया।

इस अवसर पर बहन अमनदीप कौर जी, प्रचारिका चंडीगढ़ ने सतगुरु की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सतगुरु माता जी ने ₹आत्म मंथन₹ का जो विषय दिया है, उस पर संजीदगी से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद हर गुरसिख में निराकार का वास देखते हैं, उसी प्रकार हमें हमारे परिजनों में भी निराकार का स्वरूप नजर आना चाहिए। जिससे कि प्यार के संदेश को आत्मसात कर स्वर्ग के नक्शे की जो परिकल्पना सतगुरु माता जी ने की है, उसे साकार करने में योगदान दे पाएं।

उन्होंने आगे फरमाया कि महिला, जगत की जननी, प्यार व सहनशीलता की मूर्ति होती है। मां शबरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्हें प्रभु राम के आने का पता चला तो वर्षों वर्ष प्रतिदिन बेसब्री से व सहनशीलता से इंतजार करती रही। वे सेवा की प्रतिमूर्ति के रूप में जानी जाती है। आज हम सबको भी सेवा, सिमरन व सत्संग के महत्व को समझना है, मन में वो ही चाव होना चाहिए जो मां शबरी का प्रभु राम के लिए रहा।

उन्होंने निरंकारी मिशन के इतिहास की बात करते हुए कहा कि जगतमाता बुधवंती जी, निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने संतो व सतगुरु की सेवा एवं शिक्षा को स्वयं करके दिखलाया। उन्होंने गृहस्थ में रहते हुए अध्यात्म पर चलने की जो प्रेरणा दी वो आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है।

सतगुरु माता जी के विचार का जिक्र करते हुए कहा कि संतों की शिक्षा यही है कि वास्तविक परिवर्तन बाहरी नहीं, बल्की आंतरिक होना चाहिए। सत्संग, सेवा और सिमरन के माध्यम से अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है।

इस अवसर पर उपस्थित बुजुर्ग महिलाओं जिनका महिलाओं के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान रहा उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में बहन डॉ विजय प्रभा जी ने जोनल इंचार्ज, संयोजक, मुखियों व आसपास के क्षेत्र से आई बहनों का स्वागत व धन्यवाद किया।

प्रो. आर. के. राथो, डीन (एकेडमिक्स) ने रिटायर होने वाले 19 अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मानित किया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

प्रो. आर. के. राथो, डीन (एकेडमिक्स), पीजीआई ने रिटायर होने वाले 19 अधिकारियों/कर्मचारियों को भाषण देकर और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रो. अशोक कुमार, अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक; श्री पंकज राय, कअ.र., उप निदेशक (प्रशासन); लेफ्टिनेंट कर्नल जी. एस. भट्टी, अधीक्षण अस्पताल इंजीनियर; डॉ. आर. पी. एस. भोगल, अधिकारी प्रभारी, रिसेप्शन; श्रीमती जसपाल कौर, मुख्य नर्सिंग अधिकारी; डॉ. नैन्सी साहनी, मुख्य आहार विशेषज्ञ; और श्री रवि दत्त शर्मा, वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी भी उपस्थित थे। श्री रविंदर सिंह, वित्तीय सलाहकार ने रिटायरमेंट के वित्तीय भुगतान पत्र वितरित किए।

सुशील कुमार मसोन, अस्पताल इंजीनियर (निर्माण), इंजीनियरिंग विभाग; लखविंदर कौर, उप नर्सिंग अधीक्षक, महिला चिकित्सा वार्ड; दीपो, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, राजेश कुमार, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, परमजीत कौर, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, सुदेश रानी, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, बलविंदर कौर, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, रीनल ट्रांसप्लांट एग्नेस, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, संतोष कुमारी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, अंजना वर्मा, जूनियर रिसेप्शन अधिकारी, मुख्य रिसेप्शन; दलजीत सिंह, जगदीश सिंह, कार्य परिचर, प्रेम सिंह, मुख्य रसोइया, आहार विज्ञान विभाग; विजय कुमार, नाई, स्वच्छता विभाग; खेम राज, हॉस्पिटल अटेंडेंट, अश्वनी कुमार, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ब्रह्मा देवी, हॉस्पिटल अटेंडेंट, सरबजीत कौर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, शांबिरी-ये सभी पीजीआई को अपने जीवन के 22 से 37 वर्ष समर्पित करने के बाद पीजीआई से सेवानिवृत्त हुए।

प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, भानू में 97 हिमवीर एवं हिमवीरांगनाएं हुई देश सेवा के लिए तैयार

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, भानू, पंचकूला में आज 496वें जीडी रिक्रूट (पुरुष/महिला) बैच के 22 राज्यों के 97 प्रशिक्षणार्थियों के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री अशोक नेगी, पीएमजी, महानिरीक्षक, भा.ति.सी. पुलिस, भानू रहे। ब्रिगेडियर जे.एस. गोराया, उप महानिरीक्षक, बीटीसी द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। इस भव्य समारोह में अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारी, संस्थान के पदाधिकारी एवं उनके परिवारजन तथा बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थियों के अभिभावक उपस्थित रहे।

इस परेड की कमान कांस्टेबल/जीडी (रिक्रूट) आल्ती वेंकटालक्ष्मी, 39वीं वाहिनी ने संभाली, जबकि कांस्टेबल/जीडी (रिक्रूट) गोपाल कुमार, 46वीं वाहिनी को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी घोषित किया गया। मुख्य अतिथि श्री अशोक नेगी, महानिरीक्षक, भा.ति.सी. पुलिस, भानू द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को बेसिक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं और कहा कि अब वे इस बल के ह्यहिमवीरह्ल परिवार के एक प्रशिक्षित सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपको आईटीबीपी जैसे अनुशासित बल में देश सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षण केंद्र में अर्जित ज्ञान को बनाए रखते हुए वे आगे भी सीखने का प्रयास करते रहेंगे।

इसके पश्चात बीटीसी भानू के जवानों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों के माध्यम से साहस, अनुशासन और शारीरिक क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया, जिसकी दर्शकों द्वारा अत्यधिक सराहना की गई। अशोक नेगी, महानिरीक्षक द्वारा प्रशिक्षण अवधि के दौरान समय-समय पर प्रशिक्षणार्थियों का मनोबल बढ़ाया गया।

संक्षिप्त-समाचार

मिकाडा द्वारा 31 आज से दो दिवसीय स्मार्ट सिंचाई टेक समिट-2026 का आयोजन

पंचकूला। मिकाडा, हरियाणा, भारतीय सिंचाई संघ (आई.ए.आई.) तथा हरियाणा सिंचाई संघ द्वारा तोशाम जिला भिवानी में 31 मार्च एवं 01 अप्रैल 2026 को संयुक्त रूप से दो दिवसीय ह्यस्मार्ट सिंचाई टेक समिट-2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मिकाडा पंचकूला के एसडीओ श्री विजय कुमार ने बताया कि इस सम्मेलन का उद्धेश्य नीति-निमार्ताओं, कृषि विशेषज्ञों, प्रगतिशील किसानों को एक सांझा मंच प्रदान करना है। इस सम्मेलन में कृषि प्रधान राज्यों में घटते भूजल स्तर और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान करने के बारे में विस्तार से चर्चा की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम, ऑटोमेशन, फर्टिगेशन तथा ए.आई. आधारित सिंचाई तकनीकों पर विशेषज्ञ अपने विचार सांझा करेंगे। इसके अलावा ड्रोन तकनीक, रिमोट सैसिंग और डाटा आधारित जल प्रबंधन जैसे आधुनिक उपायों का भी प्रदर्शित किया जायेगा। मिकाडा द्वारा इस सम्मेलन में ह्यपर ड्राप मोर क्रॉप, सोलर पंप योजना और कमांड एरिया डिवैल्पमैंट जैसी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जायेगी ताकि किसान इनका लाभ उठा सकें। इस सम्मेलन में किसानों को नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी जायेगी जिससे किसान अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक पैदावर प्राप्त कर सकेंगे। यह सम्मेलन उपभोक्ता समिति के सदस्यों, सरपंचों, नम्बरदारों तथा सभी कृषि भूमि धारकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। श्री विजय कुमार ने बताया कि सरकार सभी छोटे, सीमांत और सामान्य किसानों को माइक्रो इरीगेशन सिस्टम पर 85 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है। यह सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर दी जाती है जिसमें राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त टॉपअप सब्सिडी भी शामिल होती है। किसानों को केवल उपकरण की लागत का 15 प्रतिशत तथा लागू जीएसटी का भुगतान करना होता है। उन्होंने बताया की मिकाडा द्वारा ऑन-फार्म वाटर टैंक नीति 2021 में शुरू की गई है जिसे सरकार द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई है।

शिवसेना हिंदुस्तान ने हवन-यज्ञ और भजन-कीर्तन करके मनाया 23वां स्थापना दिवस

चंडीगढ़। शिवसेना हिंदुस्तान की स्थानीय इकाई ने अपने 23वें स्थापना दिवस पर मौलीजागरां कॉम्प्लेक्स स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में हवन-यज्ञ और भजन-कीर्तन चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह चौहान, जो पंजाब राज्य सचिव भी हैं, की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान पार्टी की उन्नति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए फलों और लड्डुओं का लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह चौहान ने देशभर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ह्यशेर-ए-हिंदह्ल पवन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में शिवसेना हिंदुस्तान तेजी से विस्तार कर रही है और वर्तमान में 18 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। उन्होंने कहा कि पार्टी सनातन संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन मंत्री मुरारी पाल, युवा प्रमुख अजीत चौहान, हिंदुस्तान मजदूर सेना प्रमुख कृष्ण कुमार चौहान, वार्ड-7 प्रमुख प्रकाश चंद, वार्ड प्रभारी संजय गुप्ता, मौली जागरां के ब्लॉक प्रमुख पप्पू, जसदेव सहित बड़ी संख्या में महिला शक्ति और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सीबीसी ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की

चंडीगढ़। चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल (सीबीसी) ने अपनी नई कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की है, जो संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी भूमिका को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय गुप्ता ने औपचारिक रूप से नई टीम का परिचय कराया और परिषद की प्रभावी नेतृत्व तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। नई कार्यकारिणी में नीरज बजाज को चीफ पैट्रन और जगदीश अरोड़ा को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही मुख्य सलाहकारों का एक विशिष्ट पैनल भी गठित किया गया है, जिसमें सतपाल बंसल, चंदर वर्मा, सुभाष सेठी, सतपाल गर्ग और बलदेव गोयल शामिल हैं, जो अपने व्यापक अनुभव और रणनीतिक दृष्टि से परिषद को मार्गदर्शन देंगे। संजय पाहवा और जेपीएस कालरा को महासचिव नियुक्त किया गया है, जबकि सुखपाल सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय पाहवा को मीडिया और जनसंपर्क का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। उपाध्यक्षों की टीम में कमल गुप्ता, लकी साहनी, बलबीर सिंह, परवीन गुलाटी, अवि भसीन और सुनील बंसल शामिल हैं, जो परिषद की गतिविधियों और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लखमी चंद को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त सलाहकार मंडल में अरुण तलवार, संजय दहूजा, अश्विनी खन्ना और एच.एस. गुजराल को शामिल कर इसे और मजबूत किया गया है। इसके अलावा संगठन के सुचारू संचालन और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई सचिव, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं।

लॉयन सुनील गर्ग बने लॉयंस क्लब, चंडीगढ़ सेंट्रल के अध्यक्ष

चंडीगढ़। लॉयंस क्लब, चण्डीगढ़ सेंट्रल की 45वीं चार्टर नाइट एवं जनरल बॉडी में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर (321 एफ) पीएमजेएफ लॉयन अमृत पाल सिंह जांडू, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीएमजेएफ लॉयन ललित बहल, क्लब के मुख्य सलाहकार एमजेएफ लॉयन संजय सरदाना, चेयरपर्सन लॉयन संजीव गुप्ता और विभिन्न लॉयन सदस्यों की उपस्थिति में लॉयनिस्टिक वर्ष 2026-27 के लिए नई कार्यकारी टीम का चुनाव किया गया जिसमें लॉयन सुनील गर्ग, एडवोकेट, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को अध्यक्ष चुना गया जबकि लॉयन अशोक खुराना को सचिव व लॉयन विनोद कुमार मलिक को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि लॉयंस क्लब, चण्डीगढ़ सेंट्रल प्रमुख सेवा क्लबों में से एक है जो कई कल्याणकारी गतिविधियों जैसे नेत्र दान जागरूकता, नेत्र जांच, रक्तदान, महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र, उड़ान परियोजना के तहत वंचित छात्रों को वित्तीय सहायता, पर्यावरण जागरूकता व वृक्षारोपण और इसी तरह की अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं में सक्रिय है। समारोह में बड़ी संख्या में वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट लॉयन अधिकारियों जैसे एमजेएफ लॉयन जतिंद्र सहदेव, एमजेएफ लॉयन संजीव सूद और क्षेत्रीय अध्यक्ष लॉयन सोनिया अरोड़ा के साथ-बड़ी संख्या में लायंस सदस्य और लॉयंस क्लब चंडीगढ़ सेंट्रल के लॉयन परिवार शामिल हुए।

पीजीआई में 14वीं अमृत फार्मेसी शुरू, किफायती इलाज में बना राष्ट्रीय रिकॉर्ड

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

आयुष्मान भारत जहां 44 व्हील ड्राइव की तरह बढ़ते मरीज भार को संभालने में मदद कर रहा है, वहीं अमृत योजना इलाज को किफायती बनाकर इसकी रीढ़ का काम कर रही है। यह बात पीजीआई में मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई 14वीं अमृत फार्मेसी के उद्घाटन समारोह में निदेशक प्रो.विवेक लाल ने कही। इसके साथ ही संस्थान देश के किसी भी सरकारी अस्पताल में सबसे अधिक अमृत आउटलेट्स वाला केंद्र बन गया है। नई अमृत फार्मेसी का उद्घाटन नेहरू एक्सटेंशन ब्लॉक में किया। इस अवसर पर डीन (एकेडमिक्स) प्रो. आर.के. राठो, डीन (रिसर्च) प्रो. संजय जैन, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पंकज राय और अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक प्रो. संदीप बंसल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। निदेशक प्रो. विवेक लाल ने कहा कि उन्होंने कहा कि हर मरीज को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं मिलनी चाहिए और अमृत के माध्यम से यही सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अमृत के जरिए मरीजों को मानक और प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाएं काफी रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे मरीजों का जेब से होने वाला खर्च कम हो रहा है और उन्हें इलाज में आर्थिक राहत मिल रही है। प्रो. लाल ने जानकारी दी कि संस्थान में पहले से 14 अमृत आउटलेट्स संचालित हो रहे हैं और आने वाले समय में 2 से 3 नए आउटलेट्स और स्थापित किए जाएंगे। खासकर कार्डियोलॉजी और इमरजेंसी जैसे अधिक व्यस्त विभागों में 247 अमृत सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, ताकि मरीजों को किसी भी समय दवाएं आसानी से मिल सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं, बल्कि मरीजों के हित में चलाया जा रहा एक महत्वपूर्ण अभियान है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दवाओं की उपलब्धता और रिफंड जैसी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जिनके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और संबंधित मंत्रालय से समन्वय बनाया हुआ है। पीजीआई की सेवाओं का उल्लेख करते हुए निदेशक ने कहा कि 1963 से यह संस्थान मरीजों की सेवा में अग्रणी रहा है और समय के साथ आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है, ताकि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। इस अवसर पर अमृत फार्मेसी के उपाध्यक्ष राजेश नायर भी मौजूद रहे। निदेशक ने जानकारी दी कि 27 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पीजीआई के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान न्यूरोसाइंसेज सेंटर, एडवांस्ड मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र और क्रिटिकल केयर सेंटर जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किए जाने की संभावना है। नई अमृत फार्मेसी के शुरू होने से पीजीआई में इलाज और दवाओं की लागत कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। इससे खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को सीधा लाभ पहुंचेगा और उन्हें बेहतर व किफायती इलाज उपलब्ध हो सकेगा।

बच्चों को नशे से दूर रखना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी: सतपाल शर्मा

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए उन्हें नशे जैसी बुराइयों से दूर रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे के विरुद्ध जागरूक करने के साथ-साथ कड़े कदम उठाने भी जरूरी हैं। उपायुक्त लघु सचिवालय के सभागार में नशीले पदार्थों के उपयोग की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय एनकोर्ड कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बच्चों को नशे जैसी कुरीतियों से दूर रखने पर विस्तार से चर्चा की गई। यह स्पष्ट किया गया कि विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ स्कूल समय में उनके बस्तों की जांच भी की जा सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई असामाजिक तत्व उन्हें नशे के अंधकार की ओर न धकेल सके। उपायुक्त ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को समय दें और उन पर नियमित रूप से नजर रखें, ताकि वे गलत संगत में पड़कर अपने भविष्य से खिलवाड़ न करें। अभिभावकों के साथ-साथ शिक्षकों का भी कर्तव्य है कि वे बच्चों को शिक्षा देने के साथ उनमें उच्च मूल्यों का संचार करें, ताकि वे बेहतर नागरिक बनकर देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक और सेमिनार आयोजित कर विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए।

बैठक

उपायुक्त ने संगीन अपराधों की जांच में तेजी लाने के दिए निर्देश

अपराधियों को सजा और पीड़ितों को न्याय दिलाना करें सुनिश्चित: उपायुक्त

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने लघु सचिवालय के सभागार में जिला में चिन्हित अपराधों को लेकर गठित समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होने कहा कि अपराधियों को सजा और पीड़ितों को न्याय दिलाना समिति का मुख्य उदेश्य है। उन्होने जिला में दर्ज विभिन्न संगीन अपराधों पर की गई कारवाई की समीक्षा करते हुए जांच में तेजी लाने और मामलों की गहनता और निष्पक्षता से जांच करके कानून के दायरे में अपराधियों को सजा दिलवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। बैठक के दौरान कुल 98 पुराने मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें महिलाओं के विरूद्ध अपराध, जघन्य अपराध, पासपोर्ट एक्ट, हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, एनडीपीएस कर्मशियल क्वांटिटी और गैंगवार/वाईलेशन से संबंधित मामले शामिल है। चर्चा के उपरांत बैठक में 1 नए मामलों को चिन्हित अपराध की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में मामलों से संबंधित कानूनी पहलुओं पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने निदेश दिए कि महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामलों में सभी साक्ष्यों को जुटाया जाए और माननीय न्यायालय में मजबूती से मामले की पैरवी की जाए ताकि अपराधी बच न सके और उसे कडी सजा मिले। उपायुक्त ने कहा कि ऐसे संगीन मामलों में जल्द सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया जाना चाहिए। एसीपी क्राईम श्री अरविंद कंबोज ने उपायुक्त को विस्तार से सभी मामलों के बारे में जानकारी दी। उपायुक्त ने एसीपी को निर्देश दिये कि मामलों की जांच प्रक्रिया में तेजी ला कर जल्द से जल्द निपटान किया जाए। जिन संगीन अपराधिक मामलों में आरोप तय हो चुके है, ऐसे मामलों में न्यायालय के माध्यम से अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि आपराधिक प्रवृति के लोगों में कड़ा संदेश जाए और वे इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहें। उपायुक्त ने एसीपी क्राईम को सेक्टर-5 के यवनिका पार्क के पीछे देर श्याम को, बेला विस्टा के पीछे की पार्किंग व पार्कों और सल्म बस्तियों में सिविल में पुलिस चैकिंग व पैट्रोलिंग करने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त जिला न्यायवादी आकाश तवर ने उपायुक्त को विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए मामलों में की गई कार्रवाई की प्रगति के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। जिला न्यायवादी ने उपायुक्त को आश्वासन दिलाया कि आपराधिक मामलों की जांच प्रक्रिया में और तेजी लाते हुए न्यायालय के माध्यम से अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर सेंटरल जेल अंबाला की डीएसपी गीता रानी, ड्रग इंस्पेक्टर डॉ. प्रवीण कुमार, सीएमओ आफिस से डॉ संदीप जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बिना विलम्ब हो जिलावासियों की समस्याओं का समाधान

पंचकूला। उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर में सभी अधिकारियों को बिना विलंब किए जिलावासियों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने गांव रायपुररानी के त्रिलोकपुर की बीपीएल कॉलोनी के लोगों की पानी की निकासी की समस्या पर संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों व एमिनेंट पर्सन को मौके का मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डीसी ने गांव साकेतडी के ग्रामीणों की दो गलियों में सीवरेज डालने की समस्या पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को मौके का मुआयना कर तुरंत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उपायुक्त सरकार द्वारा निर्देशित समाधान शिविर में आज जिला के लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने समाधान शिविर में आज 14 अलग-अलग लोगों की समस्याएं सुनी। कुछ का मौके पर समाधान किया बाकि समस्याओं का संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के निदेर्शानुसार जिले में लगातार समाधान शिविर चल रहे है, जिनमें जिला के अधिकारी लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कर रहे है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त कार्यालय में सोमवार व वीरवार कार्यदिवस के दिन सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने जिलवासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान करवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगराधीश जागृति, डीडीपीओ विशाल पराशर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, मत्स्य विभाग, पुलिस, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर, सिंचाई, नगर निगम तथा अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद थे।